मासिक समाचार पत्रिका
अगस्त 2026
₹ 40
वर्ष 10 / अंक 08 / लखनऊ / कुल पृष्ठ 40 (आवरण सहित)

फीफा विश्व कप 2026
फुटबॉल का महाकुंभ और नए युग की शुरुआत
P36

रसिका दुग्गल
दमदार अभिनय से मचा रहीं धूम
P38

न्यूज़ वॉच

www.newswatch.co.in

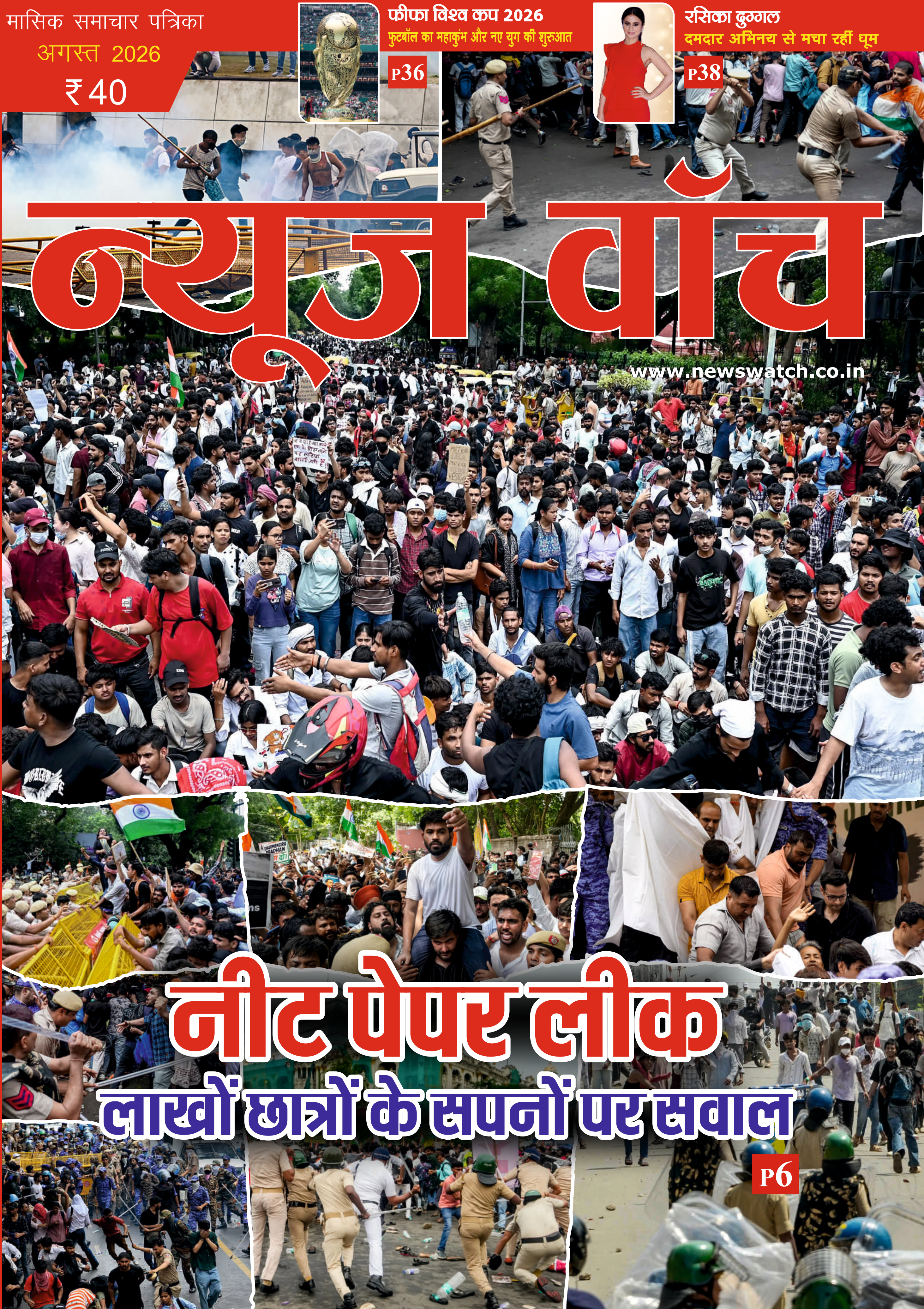

नीट पेपर लीक
लाखों छात्रों के सपनों पर सवाल

P6

C.M. COLLEGE
(ARTS & COMMERCE), DARBHANGA

(A Constituent Unit of L.N.Mithila University, Darbhanga, Bihar) ESTD:-1938

Our College is a pioneer Co-educational institution in Mithilanchal, Accredited by NAAC with Grade: "B++" (CGPA-2.77)

- Graduate Programmes in Social Sciences, Commerce and Humanities.
- Post-Graduate programmes in Eleven subjects.
- Professional Courses: BCA & BBA.
- Carrer Oriented Programme: Certificate Course in
  1. Journalism
  2. Lib. & Inf. Sc.
  3. E. Commerce
  4. Foreign Trade
  5. Creative Writing & Translation
  6. Hospitality & Catering Management
- Extracurricular activities: NCC and two units of NSS.
- Rich library (more than one lakh books and journals) with a spacious reading room.
- Boy's Hostel.
- Separate Common Room for Boys and Girls.
- A magnificent auditorium.
- Career and Counselling Cell.
- E-learning through INFLIBNET.
- A well managed modern computer lab.
- Modern English Language Lab.
- E-library.
- Smart Class.
- Well Furnished Reading Room.
- Spacious Seminar / Conference Hall.
- Free BPSC, NET, TET/CTET etc. Coaching for Minority Students.
- Wi-Fi Campus.
- C.M. College Alumni Association.
- ITEP., BA.B.ed, B.Com., B.ed.

Dr. Mushtaque Ahmad
Principal

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायेजित-अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्र

Smart Class | Well Stocked Library | Computer Lab | Modern Auditorium | Wi-Fi Campus | Hostel Facility | Counselling Cell

Address :
C.M. College (Arts & Commerce)
Darbhanga, Bihar - 846004

Contact :
+91 9431414586

संरक्षक : रवींद्र सिंह
डॉ. आरके प्रसाद
डॉ. अबसारुल हक
डॉ. आफाक हाशमी
डॉ. भारतेंदु कुमार

संपादक : मनीष कुमार
महाप्रबंधक : संतोष कुमार
सहायक संपादक : डॉ. इंबेसातुल हक
सुनील कुमार मिश्रा
अमृता कुमारी
अनन्या समहार

राज्य प्रमुख : शशिकांत राय (बिहार)
नागेंद्र सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश)
निशांत कुमार झा (दिल्ली/एनसीआर)
जितेंद्र कुमार (हरियाणा)

डिजिटल मीडिया हेड : सुजीत कुमार सिंह
ब्यूरो प्रमुख : डॉ. प्रभाकर झा (दरभंगा)
मो. हसीब (मुजफ्फरपुर)
सुमरीन राय (करनाल)
रविशंकर पांडेय (फरीदाबाद)
आशुतोष कुमार झा (पुणे)

वरिष्ठ संवाददाता : विशाल कुमार सिंह
ऋषभ सिंह चौहान
तरुण कुमार

संवाददाता : कुमार शुभम
बिनोद कुमार
अपर्णा मुखर्जी
राज कुमार झा
दिव्यांजलि वर्मा

विपणन प्रमुख : ललित शर्मा

हेड ऑफिस
जंगलवा, मां चन्द्रिका देवी रोड, बीकेटी
लखनऊ (यूपी)

ऑफिस (बिहार)
बिंदा अपार्टमेंट, 301, थर्ड फ्लोर
सगुना मोड़, दानापुर, पटना

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक मनीष कुमार द्वारा ट्रेडमैक्स प्रिंटर्स, 132/1, मारुति पुरम, निकट लेखराज मेट्रो स्टेशन, लखनऊ से मुद्रित

7905219732, 8789898428
editor@newswatch.co.in
www.newswatch.co.in

इस माह

बदलते समीकरणों के बीच
विकास की असली परीक्षा P9

संसद में बिहार के सांसदों की
दमदार मौजूदगी P10

कौशलयुक्त युवा
विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति P12

नाबालिगों के साथ
बढ़ते रेप के मामले P15

कारगिल से चंद्रयान तक
आत्मविश्वासी भारत की नई पहचान P16

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027
गठबंधन और सोशल इंजीनियरिंग पर सबका भरोसा P18

पुनर्वास की चुनौती P20
स्टेशन से सड़क पर हॉकर

स्वास्थ्य सेवा
संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व P22

जिज्ञासा से उत्कृष्टता तक
शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति
P24

P4 संपादकीय
P14 भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर राज्य की राजनीति में आया भूचाल
P26 ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता जाल बच्चों और युवाओं का बदलता संसार
P28 गंभीर चुनौती : मॉनसून की अनिश्चितता और भारत का कृषि अर्थतंत्र
P30 एक बुलबुल के घोंसले से जीवन का सबक !
P32 AI जनरेटेड म्यूजिक फ्यूचर या थ्रेट
P33 सूर्य और सात घोड़ों का रहस्य
P34 वक्त रहते पहचानें डायबिटीज की संभावना

होर्मुज संकट

भारत की प्रभावी रणनीति

होर्मुज संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है. इसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है और वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई है. संकट के तीव्र होने पर कच्चे तेल के दाम बढ़कर 90 से 111 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए. जुलाई में ही करीब 20 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई. होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव और नाकेबंदी के कारण यह क्षेत्र एक गंभीर आर्थिक संकट का केंद्र बन गया है. मार्ग बाधित होने से वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है. इससे अमेरिका और यूरोपीय देशों में खाद्य और ईंधन महंगाई तेजी से बढ़ी है. एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को भी झटका लगा है. चीन के 38 प्रतिशत और जापान एवं दक्षिण कोरिया के लगभग 70 प्रतिशत तेल आयात पर इसका सीधा बुरा असर पड़ा है. जापान में एलएनजी आपूर्ति रुकने से बिजली संकट और दक्षिण कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ गई है. शिपिंग और बीमा लागत में भी वृद्धि हुई है. युद्ध क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों का बीमा प्रीमियम अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे वैश्विक व्यापार की लागत भी बढ़ गई है. होर्मुज संकट का भारत पर भी गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है. ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक नौवहन और नाविकों की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं. भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए इस संकट का देश पर व्यापक असर पड़ रहा है. ऊर्जा आपूर्ति में गिरावट आई है. भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 40 से 50 प्रतिशत और एलपीजी का 90 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से आता है. संकट के शुरुआती चरण में मध्य-पूर्व से भारत के तेल आयात में 61 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई थी. खेती और खाद्य सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. भारत अपनी जरूरत का 40 प्रतिशत उर्वरक खाड़ी देशों से इसी रास्ते से मंगाता है. आपूर्ति टूटने से उर्वरक महंगे हो रहे हैं, जिससे किसानों की लागत बढ़ रही है और खाद्य महंगाई का खतरा पैदा हो गया है. देश को आर्थिक और राजकोषीय घाटा भी उठाना पड़ रहा है. महंगे तेल आयात के कारण भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है, जिससे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हुआ है. एशियाई विकास बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है. प्रवासी भारतीयों के लिए भी कई तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं. खाड़ी देशों में करीब 80 से 90 लाख भारतीय रहते हैं. वहां आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने से इनलोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे भारत आनेवाले विदेशी धन में कमी आ सकती है. होर्मुज संकट से निबटने के लिए भारत की रणनीति में आपूर्ति स्रोतों में विविधता, घरेलू रिफाइनरियों का अनुकूलन और सक्रिय कूटनीति शामिल हैं. इस बड़े संकट के बावजूद, सरकार की सोची-समझी रणनीतियों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका असर दुनिया के मुकाबले काफी कम (पेट्रोल की कीमतों में केवल 5.58 प्रतिशत की वृद्धि) देखा गया है. भारत ने मध्य-पूर्व पर निर्भरता कम करते हुए रूस, वेनेजुएला, अंगोला, ब्राजील और अमेरिका जैसे वैकल्पिक देशों से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है. होर्मुज से बाहर स्थित बंदरगाहों जैसे फुजैरा और यूएई-सऊदी अरब के वैकल्पिक पाइपलाइन मार्गों का उपयोग किया जा रहा है. साथ ही, यूएई के साथ रणनीतिक समझौता किया गया है. पीएम मोदी की वार्ता के बाद यूएई की तेल कंपनी के साथ तीन करोड़ बैरल तक तेल भंडार बढ़ाने और एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित करने का विशेष करार हुआ है. भारत ने इस संकट में गुटनिरपेक्ष रुख अपनाया हुआ है ताकि अमेरिका और ईरान, दोनों के साथ अपने रणनीतिक और व्यापारिक संबंध बचाए रख सके. ■

संपादकीय

मनीष कुमार

आर. के. ऑर्थो आश्रम

डॉ. आर. के. प्रसाद

डी. ऑर्थो, एम. एस. ऑर्थो (पी.एम.सी.एच.)
डी.एन.बी. (ऑर्थो.)
पी.एच.डी (ऑर्थो.)

- भूतपूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, हड्डी विभाग, डीएमसीएच, दरभंगा
- हड्डी, नस, जोड़, पोलियो, लकवा एवं गठिया रोग विशेषज्ञ
- चेयरमैन/एम.डी., आर. के. ऑर्थो आश्रम

उपलब्ध सेवाएं

हड्डी एवं जोड़ का दर्द | घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण | फ्रैक्चर एवं प्लास्टर | नस एवं स्पाइन रोग | पोलियो एवं लकवा उपचार | गठिया एवं कमर दर्द

नेशनल सिनेमा हॉल से पूरब, जूनियर होली क्रॉस स्कूल के निकट
मारवाड़ी कॉलेज वाले रास्ते में हरिजन हॉस्टल के पास
मदारपुर, दरभंगा- 846004

फोन नंबर -
7257353347 / 9547060812
आर. के. ऑर्थो आश्रम, दरभंगा
को जीपीएस में डालकर पहुंचें.

ARUNDHATI
INTERNATIONAL SCHOOL

BIHAR GOV. REG.

FREE ADMISSION

ARUNDHATI INTERNATIONAL SCHOOL (A.I.S.) ™

FULLY A/C

Play Group to VIII
C.B.S.E. English Medium

FACILITIES

- DAY CARE
- MODERN CLASS ROOM
- MONTHLY HEALTH & COUNSELLING
- DIGITAL LEARNING PROGRAM

Smart Class® BY ROBOTEL

SANTOSH KUMAR
Managing Director

New Mainpura, Pragati Nagar, Danapur, Patna
Call Us : 8521946677, 9504680300
www.aispatna.com, Email : info@aispatna.com

कवर स्टोरी

नीट पेपर लीक

लाखों छात्रों के सपनों पर सवाल

सर्वेश कुमार सिंह

भारत में मेडिकल की पढ़ाई को देश के सबसे प्रतिष्ठित और कठिन करियर विकल्पों में से एक माना जाता है. हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में शामिल होते हैं. यह परीक्षा छात्रों के वर्षों की मेहनत, लगन और भविष्य का फैसला करती है. लेकिन, जब इसी परीक्षा के प्रश्न-पत्र के लीक होने की खबर सामने आती है तो सवाल केवल एक परीक्षा की पारदर्शिता पर नहीं उठता, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था और देश की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग जाता है.

नीट पेपर लीक का मुद्दा देश-भर में इसलिए चर्चा का विषय बना, क्योंकि लाखों छात्रों ने इस परीक्षा के लिए महीनों और वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी. कई छात्र आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद पढ़ाई करते हैं. कुछ छात्र छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं. वे कोचिंग, किताबों और पढ़ाई पर अपना समय और परिवार की कमाई खर्च करते हैं. ऐसे में अगर किसी परीक्षा का प्रश्न-पत्र पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच जाता है तो मेहनत

प्रधान का त्याग-पत्र उचित निर्णय

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्याग-पत्र पूर्णतः उचित और समझदारी का निर्णय है. इसे एक वर्ग द्वारा दबाव में लिया गया निर्णय कहकर प्रचारित किया जा रहा है. वस्तुतः, यह दबाव में लिया गया निर्णय नहीं, अपितु युवाओं की वाणी और भावनाओं का सम्मान है. इस निर्णय को इस रूप में भी नहीं देखना चाहिए कि सरकार झुक गई. सरकार लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों और असहमति की भावना का सम्मान करती स्पष्ट दिखाई दी है.

यह बात बिल्कुल सही है कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जब 12 मई को इसे रद्द किया गया तो लाखों परीक्षार्थियों के सपने टूटे. वे आहत हुए, सदमे में आए, भविष्य के लिए चिंतित हुए. इसी अवसाद की स्थिति में एक दर्जन से अधिक परीक्षार्थियों ने आत्महत्या कर ली. यह इस प्रकरण का दुःखद पहलू है. इसके बाद पूरे देश की भावनाएं इस प्रकरण से जुड़ गई. परीक्षार्थियों से सहानुभूति हो गई.

ये भावनात्मक लगाव और सहानुभूति ही कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को ऊर्जा देनेवाले साबित हुए. कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापकों ने मात्र एक माह 19 दिन में आंदोलन को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया. केंद्र सरकार द्वारा 25 जुलाई को इनकी सभी मांगें मान ली गई. यह आंदोलन की उपलब्धि है. मोदी सरकार के 12 साल में यह दूसरा और सबसे कम समय चला पहला आंदोलन है जो अपनी मांगें मनवाने के बाद ही समाप्त हुआ है. पहला ऐसा आंदोलन किसानों का था, जिसमें तीन कृषि कानूनों को सरकार ने अधिसूचित करने के बाद वापस लिया था.

दोनों आंदोलनों में दो बातें समान हैं. पहली यह कि आंदोलनकारियों द्वारा बार-बार पुलिस को उकसाया गया, ऐसे हालात पैदा किए गए कि पुलिस संयम तोड़ दे और अधिकतम बल प्रयोग करे. याद है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन में घुसे पंजाब के कुछ युवाओं ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज हटा दिया था और निशान साहिब स्थापित कर दिए थे. वहां तक किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे, पुलिस जवानों को रौंदने की कोशिश हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने संयम दिखाया था. अन्यथा, हालात ऐसे थे कि लाल किले की सुरक्षा के लिए पुलिस बल द्वारा गोली भी चलाई जा सकती थी. लेकिन, पुलिस ने सूझबूझ का परिचय दिया. हालांकि, कुछ तत्व यही चाहते थे कि पुलिस संयम खो दे और विश्व में भारत की छवि को खराब करे तथा देश में माहौल बिगाड़ दे.

यही बात सीजेपी के आंदोलन में भी हुई. संसद मार्च के लिए 20 जुलाई, ठीक उसी दिन का चयन हुआ, जिस दिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू होना था. जंतर-मंतर पर धरना चल रहा था. इससे सरकार या दिल्ली पुलिस को कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन, जब संसद मार्च हुआ तो इसमें गैर-छात्रों और राजनीतिक विचार के युवाओं और कुछ

करनेवाले ईमानदार छात्रों के साथ सीधा अन्याय होता है.

पेपर लीक केवल प्रश्न-पत्र के बाहर आने की घटना नहीं है. इसके पीछे एक पूरा संगठित तंत्र काम कर सकता है, जिसमें परीक्षा से जुड़े लोग, बिचौलिये, दलाल और भ्रष्ट अधिकारी शामिल हो सकते हैं. ऐसे मामलों में अक्सर छात्रों और उनके अभिभावकों से बड़ी रकम की मांग की जाती है. कुछ लोग पैसे के बल पर परीक्षा में सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं. इससे योग्यता और मेहनत का महत्व कम होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है.

नीट जैसी परीक्षा में पेपर लीक का प्रभाव बहुत व्यापक होता है. एक ओर जहां कुछ छात्रों को अनुचित लाभ मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर लाखों ईमानदार छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है. कई छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बावजूद सीट से वंचित रह सकते हैं, जबकि अनुचित साधनों का इस्तेमाल करनेवाले छात्र उनसे आगे निकल सकते हैं. इससे छात्रों में निराशा, गुस्सा और मानसिक तनाव पैदा होता है.

• प्रश्न-पत्र लीक होने से परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर संकट
• दोषियों पर सख्त कार्रवाई और छात्रों के साथ न्याय की जरूरत

इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनेवाले छात्र अक्सर कई वर्षों तक लगातार पढ़ाई करते हैं. वे अपने दोस्तों, परिवार और सामाजिक जीवन से दूरी बनाकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं. जब उन्हें पता चलता है कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता हुई है तो उनके भीतर निराशा और असुरक्षा की भावना पैदा होती है. उन्हें लगता है कि केवल मेहनत और प्रतिभा, सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

पेपर लीक का मामला देश की परीक्षा प्रणाली में तकनीकी और प्रशासनिक कमियों को भी उजागर करता है. प्रश्न-पत्रों की छपाई, परिवहन, भंडारण और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है. इस प्रक्रिया में थोड़ी-सी लापरवाही भी लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है. इसलिए, प्रश्न-पत्र की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक, मजबूत निगरानी और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता है.

इस समस्या का समाधान केवल परीक्षा रद्द करने या दोबारा परीक्षा कराने तक सीमित नहीं होना चाहिए. सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि पेपर लीक कैसे हुआ, इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे और किस स्तर पर सुरक्षा में चूक हुई. जांच एजेंसियों को निष्पक्ष और तेज जांच करनी चाहिए. दोषी पाए जानेवाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों.

इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए. प्रश्न-पत्रों के परिवहन और भंडारण के दौरान डिजिटल ट्रैकिंग, सीसीटीवी निगरानी और स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है. परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों का सत्यापन होना चाहिए और संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखनेवाले लोगों की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए.

नीट जैसे बड़े स्तर की परीक्षा में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल भी किया

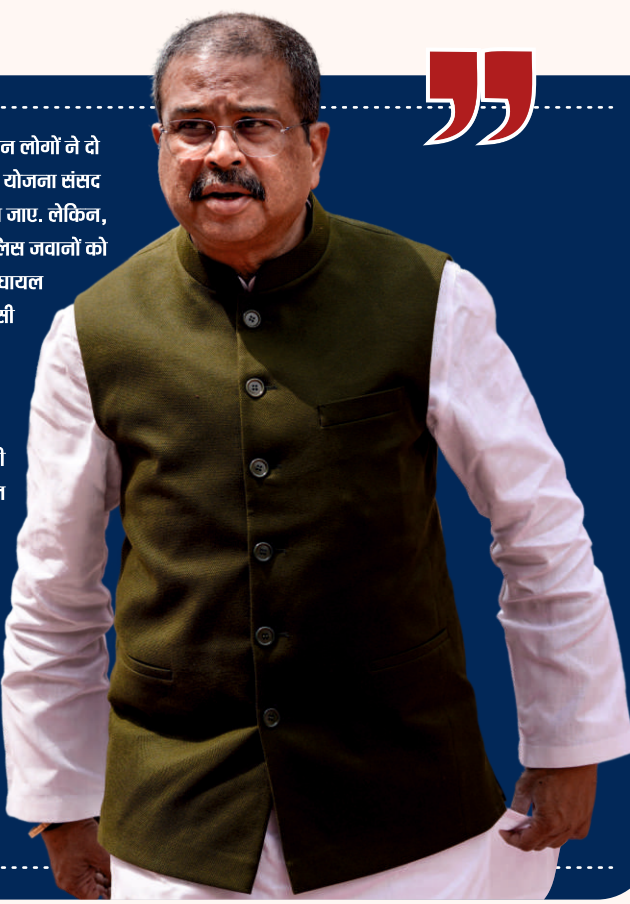

अधेड़ उम्र के लोगों की घुसपैठ हो गई. ये हर हाल में माहौल बिगाड़ने पर आमादा थे. संसद कूच में इन लोगों ने दो बैरिकेड तोड़ दिए, तीसरे को तोड़कर संसद पहुंचना चाहते थे, जहां मॉनसून सत्र शुरू हुआ था. इनकी योजना संसद भवन में घुसने की थी, ताकि पुलिस नेपाल की तरह अधिकतम बल प्रयोग कर दे, यानी फायरिंग हो जाए. लेकिन, पुलिस ने इन्हें जब तीसरे बैरिकेड पर रोका तो ये पुलिस से भिड़ गए. यहां पुलिस पर पथराव हुआ. पुलिस जवानों को पीटा गया, हमले किए गए. जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस पूरे टकराव में 118 पुलिसकर्मी घायल हुए. आंदोलनकारी भी घायल हुए. पुलिस ने उतना ही बल प्रयोग किया, जितना सामान्य रूप से किसी भी जुलूस या मार्च को संसद जाने से रोकने के लिए किया जाता है. यहां भी पुलिस ने संयम दिखाया, अन्यथा हालात बहुत खराब हो सकते थे.

दोनों आंदोलनों में दूसरी समान बात यह है कि सरकार ने मांगें मानने के लिए उस खुफिया इनपुट को महत्व दिया, जिसमें बताया गया कि आंदोलन में बाहरी हस्तक्षेप हो गया है. बाहरी और देशविरोधी शक्तियां आंदोलन को उग्र कर अशांति पैदा करना चाहती हैं. ये तत्व चिह्नित भी किए गए जो आंदोलन को बैक डोर से सपोर्ट कर रहे थे. दोनों आंदोलनों में मांगों से अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बनाने की कोशिश हुई.

शिक्षा मंत्री पद से त्याग-पत्र देते समय धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि वह राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर त्याग-पत्र दे रहे हैं. आंदोलन के नाम पर कुछ लोग अशांति पैदा कर सकते हैं. दूसरी तरफ, आंदोलन समाप्ति पर देश-भर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हुई हैं. सभी ने त्याग-पत्र और आंदोलन समाप्ति को उचित बताया है. लेकिन, यह युवाओं की अच्छी छवि लेकर समाप्त नहीं हुआ. आंदोलन में अश्लील भाषा, अश्लील पोस्टर और अभद्रता, आक्रामकता और पत्रकारों पर हमले की घटनाएं हुईं जो किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती हैं. इस पहलू पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को विचार करना चाहिए. भविष्य की राजनीति के लिए वे ऐसे तत्वों से दूरी बना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभिजीत दीपके को अंततः राजनीति ही करनी है.

जा सकता है. प्रश्न-पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया में डिजिटल सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है. हालांकि, तकनीक के इस्तेमाल के साथ साइबर सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देना होगा. किसी भी तकनीकी व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए लगातार निगरानी और स्वतंत्र ऑडिट जरूरी है.

इस मामले में सरकार और परीक्षा आयोजित करनेवाली संस्थाओं की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है. छात्रों और अभिभावकों को परीक्षा प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए. अगर, किसी परीक्षा में अनियमितता की शिकायत सामने आती है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत जांच की जानी चाहिए. पारदर्शिता और जवाबदेही से ही छात्रों का भरोसा वापस जीता जा सकता है.

नीट पेपर लीक का मुद्दा हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया है. मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या सीमित है, जबकि उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है. लाखों छात्र कुछ हजार सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं. इस कारण परीक्षा में सफलता छात्रों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन जाती है. ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की अनियमितता छात्रों के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालती है.

हालांकि, परीक्षा में गड़बड़ी के कारण सभी छात्रों को दोषी मानना भी उचित नहीं है. जिन छात्रों ने ईमानदारी से परीक्षा दी है, उनके हितों की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है. किसी भी निर्णय में यह ध्यान रखना चाहिए कि निर्दोष छात्रों को अनावश्यक परेशानी न हो. परीक्षा रद्द करने या दोबारा आयोजित करने जैसे फैसलों का प्रभाव लाखों छात्रों पर पड़ता है, इसलिए ऐसे निर्णय तथ्यों और निष्पक्ष जांच के आधार पर होने चाहिए.

नीट पेपर लीक का मामला केवल छात्रों और सरकार के बीच का विवाद नहीं है. यह देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है. आज के छात्र ही कल के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे. अगर, उन्हें शुरुआत में ही यह संदेश मिले कि मेहनत से ज्यादा पैसा और संपर्क महत्वपूर्ण हैं तो यह समाज के लिए बेहद खतरनाक संकेत होगा. इसलिए, जरूरत है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जाए. दोषियों को कड़ी सजा मिले, जांच निष्पक्ष हो और छात्रों के साथ न्याय किया जाए. साथ ही, भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी और प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए.

अंततः, नीट पेपर लीक का मामला हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाएं केवल अंक और रैंक का खेल नहीं हैं. इनके पीछे लाखों छात्रों के सपने, परिवारों की उम्मीदें और देश का भविष्य जुड़ा होता है. इसलिए, परीक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता. एक मजबूत और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली ही युवाओं को यह विश्वास दिला सकती है कि भारत में मेहनत, प्रतिभा और ईमानदारी का सम्मान होता है. ■

बदलते समीकरणों के बीच विकास की असली परीक्षा

मानसी प्रिया

बिहार की राजनीति हमेशा से देश की राजनीति का केंद्र रही है. यहां होनेवाले राजनैतिक घटनाक्रम केवल राज्य तक सीमित नहीं रहते, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं. स्वाधीनता से पहले बिहार का बंगाल से पृथक होना, इसके बाद ओडिशा का बिहार से अलग होना एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार तथा झारखंड का पृथक्करण, सभी घटनाओं ने कहीं-न-कहीं देश की राजनैतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है.
वर्ष 2026 में बिहार एक बार फिर राजनैतिक हलचलों के दौर से गुजर रहा है. सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों अपनी-अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं, जबकि जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राजनैतिक दल चुनावी नारों से आगे बढ़कर विकास, रोजगार और सुशासन जैसे वास्तविक मुद्दों पर कितना ध्यान देते हैं.
हाल के महीनों में बिहार की राजनीति में कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं. विभिन्न राजनैतिक दलों में नेताओं का आना-जाना, संगठनात्मक फेरबदल और उपचुनावों की तैयारियों ने राजनीतिक माहौल को और अधिक सक्रिय बना दिया है.
हालांकि, यह लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इन राजनीतिक गतिविधियों का लाभ आम जनता तक पहुंच पाएगा?
बिहार लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे एवं पलायन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है. राज्य के लाखों युवा आज भी बेहतर रोजगार और उच्चस्तरीय शिक्षा की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं. हर वर्ष यहां जनसंख्या बढ़ती जा रही है तथा महिला लिंगानुपात घटता जा रहा है जो चिंताजनक है.
यदि राजनीतिक दल वास्तव में जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं तो उन्हें चुनावी भाषणों से आगे बढ़कर रोजगार सृजन, औद्योगिक निवेश और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस पहल करनी होगी.
बिहार हर वर्ष बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करता है. उत्तर बिहार के कई जिले लगातार बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिससे लाखों लोगों का जीवन और आजीविका प्रभावित होती है. यह केवल प्राकृतिक समस्या नहीं बल्कि प्रभावी योजना, बेहतर जल प्रबंधन और दीर्घकालिक नीतियों की भी परीक्षा है. राज्य सरकार को राहत कार्यों के साथ-साथ स्थायी समाधान पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा.
सरकार को औद्योगिक निवेश के साथ-साथ अन्य योजनाओं जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, सतत विकास के क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्य करने की जरूरत है. साथ ही, मूलभूत सुविधाओं को और मजबूती प्रदान करना चाहिए.
आज का मतदाता पहले की तुलना में अधिक जागरूक है. सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने लोगों को जानकारी तक आसान पहुंच दी है. अब मतदाता केवल जातीय या पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि सरकार के कामकाज, पारदर्शिता और विकास के आधार पर भी अपनी राय बनाते हैं. यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है.
हालांकि, कई बार इसमें आमूलचूल परिवर्तन देखा जा सकता है. विपक्ष की भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है. एक मजबूत विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाता है और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाता है. इसलिए, आवश्यक है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हो और उसका केंद्र जनता का हित बने, न कि केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप. यहां हम दबाव समूह को भी उचित स्थान देंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सरकार और जनता की मध्यस्थता कर राजनीति को और सुदृढ़ करते हैं.

जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राजनैतिक दल चुनावी नारों से आगे बढ़कर विकास, रोजगार और सुशासन जैसे वास्तविक मुद्दों पर कितना ध्यान देते हैं.

बिहार के पास अपार संभावनाएं हैं. कृषि, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, औद्योगीकरण और मानव संसाधन के क्षेत्र में यह र७ाज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है. इसके लिए आवश्यक है कि सभी राजनैतिक दल विकास को साझा एजेंडा बनाएं. यदि सरकार और विपक्ष, दोनों मिलकर राज्यहित को सर्वोपरि रखें तो बिहार आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है. लोकतंत्र में सत्ता बदलना सामान्य बात है, लेकिन जनता की अपेक्षाएं नहीं बदलतीं. जनता हमेशा बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण, रोजगार के अवसर एवं पारदर्शी शासन चाहती है जो वस्तुतः उसका अधिकार भी है और यही किसी भी सरकार की वास्तविक कसौटी होती है.
बिहार की राजनीति आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है. यह समय केवल राजनैतिक समीकरण बदलने का नहीं, बल्कि विकास की नई इबारत लिखने का भी है. आवश्यकता इस बात को आत्मसात करने की है कि विश्व में गणतंत्र सबसे पहले बिहार की धरा पर ही अंकुरित हुआ था. 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की नीति के साथ यदि राजनैतिक नेतृत्व दूरदर्शिता, पारदर्शिता, ईमानदारी, जनहित और सहभागिता को प्राथमिकता देगा तो बिहार आनेवाले वर्षों में देश के सबसे तेजी से आगे बढ़नेवाले राज्यों में अपनी पहचान बना अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहरा सकता है. लोकतंत्र की असली जीत तभी होगी, जब राजनीति का केंद्र सत्ता नहीं, बल्कि जनता का कल्याण होगा. ■

संसद में बिहार के सांसदों की दमदार मौजूदगी

संजय झा, धर्मशीला गुप्ता और शांभवी चौधरी

> "राज्यसभा में संजय झा और धर्मशीला गुप्ता एवं लोकसभा में शांभवी चौधरी ने अपनी अलग पहचान कायम की है. उपस्थिति, बहसों में सक्रियता और प्रश्न पूछने के मानकों पर इनका अब तक का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है."

राज्यसभा में संजय झा का जबरदस्त प्रदर्शन, उपस्थिति और सवाल पूछने में राष्ट्रीय औसत से आगे

बिहार से राज्यसभा सदस्य और जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने राज्यसभा में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सक्रिय संसदीय भूमिका निभाते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है. संसद की कार्यवाही से जुड़े उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने न केवल सदन में नियमित उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रश्न पूछकर बिहार और देश से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया.

राज्यसभा के संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार, संजय झा की उपस्थिति 92 प्रतिशत रही है जो राष्ट्रीय औसत 79 प्रतिशत तथा बिहार के औसत 82 प्रतिशत से अधिक है. विभिन्न सत्रों में उनकी नियमित मौजूदगी यह दर्शाती है कि उन्होंने सदन की कार्यवाही को गंभीरता से लिया और हर महत्वपूर्ण चर्चा में भागीदारी निभाई.

निशांत कुमार झा

प्रश्न पूछने के मामले में भी उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है. अब तक उन्होंने 132 प्रश्न पूछे हैं, यह संख्या राज्यसभा के राष्ट्रीय औसत से अधिक है. उनके सवालों का दायरा केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की आधारभूत संरचना, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, जल संसाधन, पर्यावरण और आर्थिक विकास जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों तक रहा. बिहार के संदर्भ में उन्होंने दरभंगा एम्स, बिहार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आवश्यकता, रेलवे परियोजनाओं, जनऔषधि केंद्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा.

सदन की बहसों में भी संजय झा ने प्रभावी भागीदारी निभाई. उन्होंने केंद्रीय बजट, राष्ट्रपति के अभिभाषण, रेल, शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर अपनी बात रखते हुए बिहार के हितों को प्रमुखता से उठाया. विभिन्न नीतिगत चर्चाओं के दौरान उनके सुझावों और हस्तक्षेपों को गंभीरता से सुना गया.

मिथिला और उत्तर बिहार से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई. राज्यसभा में उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने, महाकवि विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण, मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में लाने, उत्तर बिहार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना तथा तिरहुता (वैदेही) लिपि को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थान दिलाने जैसे विषयों को मजबूती से उठाया. इन मुद्दों को मिथिला के विकास और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा में संजय झा का प्रदर्शन केवल उपस्थिति तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने प्रश्नों, विशेष उल्लेखों और बहसों के माध्यम से बिहार के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी अपनी सक्रियता दिखाई. संसदीय आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उपस्थिति और प्रश्न पूछने के मामले में उनका प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है.

कुल मिलाकर, राज्यसभा में संजय झा का अब तक का संसदीय रिपोर्ट कार्ड उन्हें एक सक्रिय, अध्ययनशील और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठानेवाले सांसद के रूप में स्थापित करता है. बिहार, विशेषकर मिथिला और उत्तर बिहार से जुड़े विकासात्मक मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में उनकी भूमिका उल्लेखनीय मानी जा रही है.

संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि जनभावनाओं और क्षेत्रीय अपेक्षाओं को राष्ट्रीय विमर्श तक पहुंचाने का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक माध्यम भी है. ऐसे में किसी सांसद का मूल्यांकन केवल राजनीतिक भाषणों से नहीं, बल्कि उसकी संसदीय सक्रियता, उपस्थिति, प्रश्नों, बहसों और जनहित

राज्यसभा में डॉ. धर्मशीला गुप्ता : उपस्थिति मजबूत, बहसों में मुखर, बिहार के मुद्दों को दिलाई राष्ट्रीय पहचान

के मुद्दों को उठाने की क्षमता से किया जाता है. बिहार से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता का संसदीय रिकॉर्ड इसी कसौटी पर एक दिलचस्प तस्वीर पेश करता है.

राज्यसभा के उपलब्ध संसदीय आंकड़ों के अनुसार, डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने सदन की कार्यवाही में 89 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराई है. यह राष्ट्रीय औसत और बिहार के औसत, दोनों से बेहतर है. कई सत्रों में उनकी शत-प्रतिशत उपस्थिति यह दर्शाती है कि उन्होंने सदन की कार्यवाही को गंभीरता से लिया और नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया.

सिर्फ उपस्थिति ही नहीं, सदन में बहसों के दौरान भी डॉ. गुप्ता लगातार सक्रिय रहीं. उन्होंने विभिन्न विधेयकों, केंद्रीय बजट, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और शिक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी. संसदीय रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने अब तक 80 चर्चाओं में हिस्सा लिया है जो उन्हें सक्रिय वक्ताओं की श्रेणी में खड़ा करता है.

बिहार, विशेषकर मिथिला क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में भी उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही. उन्होंने दरभंगा में एम्स की स्थापना में तेजी लाने, उत्तर बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, रेलवे परियोजनाओं, मखाना उत्पादन को बढ़ावा, मैथिली भाषा के संरक्षण तथा महिलाओं और बच्चों से जुड़े विषयों पर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित किया. समय-समय पर उन्होंने विशेष उल्लेख और अन्य संसदीय माध्यमों से क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया.

हालांकि, संसदीय प्रदर्शन का एक पक्ष ऐसा भी है, जहां सुधार की संभावना दिखाई देती है. प्रश्नकाल में उनकी सक्रियता बहसों और उपस्थिति की तुलना में कम रही है. उपलब्ध संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने अब तक 57 प्रश्न पूछे हैं, जबकि राज्यसभा का राष्ट्रीय औसत इससे अधिक है. संसदीय विशेषज्ञों का मानना है कि प्रश्नकाल सरकार की जवाबदेही तय करने का सबसे प्रभावी माध्यम होता है. यदि इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ती है तो उनका संसदीय प्रभाव और व्यापक हो सकता है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी सांसद की वास्तविक सफलता केवल सदन में उठाए गए मुद्दों से नहीं, बल्कि उन मुद्दों के धरातल पर दिखनेवाले परिणामों से भी तय होती है. ऐसे में दरभंगा एम्स, उत्तर बिहार की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सेवाओं और मिथिला क्षेत्र के विकास से जुड़े जिन विषयों को डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने संसद में उठाया है, उन्हें मूर्त रूप दिलाना आनेवाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी.

संसदीय रिकॉर्ड का समग्र विश्लेषण बताता है कि डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने अपने कार्यकाल में नियमित उपस्थिति और प्रभावशाली बहसों के माध्यम से एक सक्रिय सांसद की पहचान बनाई है. वहीं, प्रश्न पूछने के मामले में अभी और सक्रियता की गुंजाइश बनी हुई है. यदि आनेवाले सत्रों में वह प्रश्नकाल में भी समान ऊर्जा के साथ भागीदारी बढ़ाती हैं तो उनका संसदीय रिपोर्ट कार्ड और अधिक प्रभावशाली बन सकता है.

इसमें कोई शक नहीं कि डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने राज्यसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ-साथ बिहार के मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने का प्रयास किया है. अब जनता की निगाह इस बात पर रहेगी कि संसद में उठाई गई आवाज विकास की ठोस उपलब्धियों में कितनी तेजी से बदलती है.

पहली बार लोकसभा पहुंचीं समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने 18वीं लोकसभा के शुरुआती सत्रों में सक्रिय संसदीय भूमिका निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई है. संसद की कार्यवाही से जुड़े उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि उपस्थिति, प्रश्न पूछने और बहस में भागीदारी जैसे प्रमुख पैमानों पर उनका प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती संसद में उठाए गए मुद्दों को समस्तीपुर के लिए ठोस विकास योजनाओं में बदलने की होगी.

संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार, शांभवी चौधरी की लोकसभा में 96 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई है. यह राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है. पहले ही कार्यकाल में नियमित उपस्थिति दर्ज कर उन्होंने सदन की कार्यवाही के प्रति अपनी गंभीरता दिखाई है.

प्रश्न पूछने के मामले में भी उन्होंने सक्रियता दिखाई है. अब तक 190 प्रश्न पूछकर उन्होंने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है. उनके सवालों में रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास, सामाजिक न्याय, संचार, खेल, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़े विषय प्रमुख रहे. समस्तीपुर और उत्तर बिहार से जुड़े रेल संपर्क, सड़क परियोजनाओं और कृषि विकास के मुद्दों को भी उन्होंने सदन में उठाया.

संसदीय बहसों में भी उनकी भागीदारी उल्लेखनीय रही. अब तक 38 चर्चाओं में हिस्सा लेकर उन्होंने बजट, कृषि, रेलवे, सामाजिक न्याय और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी. इसके अलावा, नियम-377 और विशेष उल्लेख के माध्यम से उन्होंने समस्तीपुर के विकास से जुड़े कई मुद्दों को संसद के पटल पर रखा.

पहली बार सांसद बनने के बावजूद शांभवी चौधरी ने संसदीय कार्यवाही में सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई है.

18वीं लोकसभा में शांभवी चौधरी का दमदार आगाज, उपस्थिति और सवाल पूछने में औसत से आगे

हालांकि, अब जनता की अपेक्षा केवल संसद में सवाल पूछने या बहस तक सीमित नहीं है. समस्तीपुर लंबे समय से बाढ़, रोजगार की कमी, औद्योगिक विकास का न होना, स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर स्थिति और आधारभूत ढांचे का अभाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. ऐसे में इन मुद्दों पर केंद्र सरकार से ठोस स्वीकृतियां और परियोजनाएं दिलाना उनकी अगली बड़ी परीक्षा होगी.

संसदीय प्रदर्शन के आंकड़े किसी सांसद की सक्रियता का महत्वपूर्ण संकेत जरूर होते हैं, लेकिन अंतिम मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि संसद में उठाए गए मुद्दों का कितना असर क्षेत्र के विकास पर दिखाई देता है. आनेवाले सत्रों में शांभवी चौधरी की भूमिका इसी कसौटी पर परखी जाएगी.

दरअसल, 18वीं लोकसभा के शुरुआती दौर में शांभवी चौधरी ने एक सक्रिय सांसद के रूप में अपनी पहचान बनाई है. अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि उनकी संसदीय सक्रियता समस्तीपुर के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान में कितनी प्रभावी साबित होती है. ■

कौशलयुक्त युवा
विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति

भारत के भविष्य की चर्चा जब भी होती है, एक शब्द बार-बार सामने आता है- युवा. यह केवल एक आयु वर्ग का नाम नहीं है, बल्कि ऊर्जा, उत्साह, नवाचार और परिवर्तन की उस शक्ति का प्रतीक है जो किसी भी राष्ट्र की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखती है. आज जब विश्व के अनेक विकसित देश घटती जन्म दर, वृद्ध होती आबादी और श्रमशक्ति की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब भारत के पास युवाओं का विशाल भंडार है. यही कारण है कि भारत की युवा आबादी को 21वीं सदी की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पूंजी कहा जा रहा है.

डॉ. इंबेसातुल हक

भारत की सड़कों पर दौड़ते सपने, विश्वविद्यालयों में आकार लेतीं आकांक्षाएं, प्रयोगशालाओं में जन्म लेते नवाचार, खेतों में नई तकनीकों के साथ प्रयोग करते युवा किसान, डिजिटल मंचों पर अपनी पहचान बनाते उद्यमी और वैश्विक कंपनियों में नेतृत्व की भूमिका निभाते भारतीय पेशेवर, ये सभी मिलकर उस नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जो आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है. यह भारत केवल जनसंख्या के आधार पर बड़ा नहीं है, बल्कि संभावनाओं के आधार पर भी विशाल है.

हाल के वर्षों में भारत ने जिस गति से डिजिटल परिवर्तन का अनुभव किया है, वह विश्व के लिए अध्ययन का विषय बन गया है. मोबाइल फोन और इंटरनेट ने ज्ञान, सूचना और अवसरों तक पहुंच को पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान बना दिया है. छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी अब वे अवसर उपलब्ध हैं जो कभी केवल महानगरों तक सीमित थे. डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों ने जीवन और कार्य, दोनों की प्रकृति को बदल दिया है. इन परिवर्तनों के केंद्र में युवा ही हैं.

फिर भी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा है. क्या केवल बड़ी युवा आबादी किसी राष्ट्र को विकसित बना सकती है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' है. इतिहास बताता है कि जनसंख्या तभी शक्ति बनती है, जब उसे सही दिशा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यक कौशल प्राप्त हों. यदि युवा ऊर्जा को सही मार्ग न मिले तो वही शक्ति चुनौती में बदल सकती है. इसलिए, भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी युवा आबादी को कौशलयुक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है.

आज रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. एक समय था, जब डिग्री को सफलता का पर्याय माना जाता था. विश्वविद्यालय से निकलते ही नौकरी मिलने की उम्मीद की जाती थी. लेकिन, वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल चुकी हैं. उद्योग जगत केवल प्रमाण-पत्रों से संतुष्ट नहीं है. उसे ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो समस्याओं का समाधान कर सकें, नई परिस्थितियों में स्वयं को ढाल सकें, तकनीक का प्रभावी उपयोग कर सकें और नवाचार की क्षमता रखते हों. यही कारण है कि कौशल विकास आज राष्ट्रीय विमर्श का

महत्वपूर्ण विषय बन चुका है.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं. दूसरी ओर, अनेक पारंपरिक नौकरियों का स्वरूप भी बदल रहा है. आनेवाले समय में वही युवा आगे बढ़ेंगे जो निरंतर सीखने की क्षमता रखते होंगे. सीखना अब शिक्षा का एक चरण नहीं, बल्कि जीवनभर चलनेवाली प्रक्रिया बन चुका है. इस नई दुनिया में अनुकूलनशीलता, रचनात्मकता और तकनीकी दक्षता सबसे बड़ी पूंजी बन गई है.

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत में कौशल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया गया है. स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहल केवल सरकारी योजनाएं नहीं हैं, बल्कि भविष्य के भारत के निर्माण की आधारशिलाएं हैं. इन कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इनका उद्देश्य युवाओं को नौकरी खोजनेवाला नहीं, बल्कि अवसरों का सृजनकर्ता बनाना है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भी शिक्षा और कौशल के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया है. लंबे समय तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर यह आरोप लगाया जाता रहा कि यह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करती है, जीवन के लिए नहीं. नई शिक्षा नीति ने इस सोच को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है. विद्यालय स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम, परियोजना आधारित शिक्षण और इंटर्नशिप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो केवल ज्ञान अर्जित न करें, बल्कि उसे व्यवहार में भी उतार सकें.

शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं होता. शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने, निर्णय लेने और समाज के प्रति उत्तरदायी बनने की क्षमता प्रदान करती है. जब शिक्षा कौशल से जुड़ती है तो वह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है. यही आत्मनिर्भरता विकसित भारत की आधारशिला है. आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा और कौशल को एक-दूसरे का पूरक माना जाए, न कि अलग-अलग अवधारणाएं.

भारतीय युवाओं की सबसे बड़ी विशेषताओं में उनकी उद्यमशीलता भी शामिल है. पिछले कुछ वर्षों में देश में स्टार्टअप संस्कृति का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है. छोटे शहरों और कस्बों से निकलकर युवा उद्यमी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं. कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-कॉमर्स, फिनटेक और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में युवाओं द्वारा विकसित नवाचार यह सिद्ध करते हैं कि भारतीय युवा केवल अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि उन्हें स्वयं निर्मित भी करते हैं.

यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं है, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी दूरगामी हैं. जब कोई युवा स्वयं का उद्यम स्थापित करता है तो वह केवल अपनी आजीविका सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करता है. वह समाज में आत्मविश्वास और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है. आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को वास्तविक धरातल पर उतारने में युवा उद्यमियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.

ग्रामीण भारत में भी परिवर्तन की एक नई कहानी लिखी जा रही है. लंबे समय तक यह धारणा रही कि अवसर केवल शहरों में उपलब्ध हैं. लेकिन, आज यह स्थिति तेजी से बदल रही है. कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, ग्रामीण पर्यटन और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं. अनेक युवा आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर कृषि और ग्रामीण व्यवसायों को लाभकारी बना रहे हैं. वे परंपरा और तकनीक के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं.

यदि ग्रामीण युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधन, वित्तीय सहायता और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो वे स्थानीय स्तर पर विकास के नए मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं. इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि शहरों की ओर होनेवाला

शेष पृष्ठ-17 पर...

> भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है. इसे विश्व की 'युवा शक्ति' भी कहा जाता है. यदि इस जनसांख्यिकीय लाभ का सही उपयोग किया जाए तो आनेवाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है. करोड़ों युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, नवाचार और नई सोच को देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ी पूंजी माना जा रहा है. भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश के कुशल, प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर युवा निभानेवाले हैं.

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर

राज्य की राजनीति में आया भूचाल

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के बाद बिहार की राजनीति में जिस तरह का माहौल बना है, उसने सत्ता और विपक्ष, दोनों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुई इस घटना के बाद शुरू में इसे एक सामान्य पुलिस कार्रवाई बताया गया, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो सामने आए और स्थानीय लोगों के बयान सामने आने लगे, मामला लगातार तूल पकड़ता गया. अब यह केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की राजनीति का चर्चित मुद्दा बन चुका है.

भरत तिवारी के परिवार और समर्थकों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने लगातार इस मामले को उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. विपक्ष का कहना है कि यदि पुलिस कार्रवाई पूरी तरह सही थी तो फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं. विपक्ष इस मुद्दे को न्याय, मानवाधिकार और कानून के राज से जोड़कर जनता के बीच ले जा रहा है.

इस बीच मामले में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए सरकार ने विशेष जांच कमिटी का गठन कर दिया है, ताकि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो सके. शुरुआती जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामले से जुड़े कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है. भरत तिवारी पर पहली गोली चलानेवाले एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. सरकार का कहना है कि यदि जांच में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही अथवा गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दिलचस्प बात यह है कि भरत तिवारी के समर्थन में केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के अंदर से भी आवाजें सुनाई देने लगी हैं.

आशुतोष कुमार झा

भाजपा और जेडीयू के कई नेताओं ने सीधे या परोक्ष रूप से निष्पक्ष जांच की मांग की है. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह मामला केवल राजनीतिक विरोध का नहीं, बल्कि सरकार के भीतर भी चिंता का विषय बन चुका है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुंचे. मुख्यमंत्री की इस मुलाकात को सरकार की ओर से जनता का विश्वास बहाल करने की कोशिश के रूप में देखा गया. हालांकि, राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी जारी है कि यदि जांच में पुलिस की बड़ी चूक सामने आती है या सरकार इस पूरे मामले को प्रभावी ढंग से संभालने में विफल रहती है तो इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी सरकार पर भी आएगी. बढ़ते जनदबाव और विपक्ष के लगातार हमलों के बीच यह मामला आनेवाले समय में बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, भाजपा या जेडीयू की ओर से नेतृत्व परिवर्तन या किसी बड़े राजनीतिक फैसले को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है.

भाजपा के लिए यह मामला एक चुनौती और अवसर, दोनों माना जा रहा है. यदि सरकार जांच कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर पारदर्शी कार्रवाई करती है और दोषियों को सजा मिलती है तो यह संदेश जाएगा कि कानून सबके लिए समान है. वहीं, यदि जांच में अनावश्यक देरी होती है या लोगों को पारदर्शिता पर संदेह होता है तो विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकता है. जेडीयू के अंदर भी कई नेताओं का मानना है कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के पीछे भरत तिवारी प्रकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. यदि यह मुद्दा लंबे समय तक चर्चा में बना रहता है तो विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है. दूसरी ओर, यदि सरकार निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये जनता का भरोसा जीतने में सफल रहती है तो यह संकट उसके लिए अवसर भी साबित हो सकता है.

बिहार की राजनीति में अक्सर ऐसे मुद्दे बड़े बदलाव का कारण बनते रहे हैं. इसलिए, भरत तिवारी एनकाउंटर को केवल एक पुलिस कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा रहा है. पूरे राज्य की निगाहें जांच रिपोर्ट और आगे होनेवाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं. फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं सरकार जांच और कार्रवाई के जरिये जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है. अब यह देखना होगा कि जांच के अंतिम निष्कर्ष क्या सामने आते हैं और उनका बिहार की राजनीति पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है.■

नाबालिगों के साथ बढ़ते रेप के मामले

बच्चों के खिलाफ यौन अपराध समाज के लिए एक गहरा कलंक और अत्यंत चिंता का विषय है. मासूमों को सुरक्षा देने के दावों के बीच एनसीआरबी के आंकड़े और आएदिन सामने आनेवाली घटनाएं इस भयावह वास्तविकता को उजागर करती हैं. यह समस्या केवल एक कानूनी अपराध नहीं है, बल्कि यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को पूरी तरह तबाह कर देती है.

अपर्णा मुखर्जी

पूरे भारत में रेप के कई तरह के मामले लगातार हमारे सामने आते रहते हैं. जब हम देश के अलग-अलग राज्यों में नाबालिगों के साथ रेप की वीभत्स घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो यह हमारी आत्मा को झकझोर देता है, हमारी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं. साल-दर-साल भारत में रेप के मामले बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि नाबालिगों के साथ रेप के मामले भी बढ़ रहे हैं.

रेप करने वाले सभी अपराधियों की सोच एक जैसी नहीं होती और नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के पीछे उनकी वजहें भी अलग-अलग होती हैं, इसलिए अलग-अलग अपराधियों की सोच को समझना एक चुनौती है. एक बात तो साफ है कि रेप करनेवालों की सोच बहुत गंदी होती है और उनका दिमाग नाबालिगों के शरीर के साथ बेरहमी से खिलवाड़ करने के अलावा कुछ नहीं जानता. रेप करनेवालों की सोच चाहे कैसी भी हो, उन्हें कठोरतम सजा मिलनी चाहिए.

नाबालिगों के साथ रेप

रेप एक ऐसा हिंसक व्यवहार है जो जेंडर से जुड़ा है. ज्यादातर यौन हिंसा करनेवाले, पुरुष होते हैं और ज्यादातर पीड़ित, महिलाएं होती हैं. रेप महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सबसे आम रूप है और यह लंबे समय से इंसानी संस्कृति का हिस्सा रहा है. यह महिला की शारीरिक गरिमा का गंभीर उल्लंघन है और एक तरह का टॉर्चर भी हो सकता है.

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद, भारत महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम रहा है. भारत में महिलाओं के खिलाफ होनेवाले अपराधों में रेप चौथे नंबर पर आता है. अनुमान है कि दुनिया-भर में लगभग 35 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी जिंदगी में किसी-न-किसी तरह के यौन उत्पीड़न का सामना किया है. रेप के बारे में डेटा उपलब्ध करानेवाले ज्यादातर देशों की रिपोर्ट बताती है कि यौन हिंसा का शिकार होनेवाली 40 प्रतिशत से भी कम महिलाएं मदद मांगती हैं. इनमें से 10 प्रतिशत से भी कम महिलाएं कानून लागू करनेवाली एजेंसियों से मदद मांगती हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि बड़ी तादाद में यौन हिंसा की शिकार महिलाएं अपने साथ हुए अपराध की न तो रिपोर्ट करती हैं और न ही सामने आती हैं. ऐसा समाज द्वारा रेप पीड़िताओं पर डाले जानेवाले शर्म और कलंक के बोझ के कारण होता है.

साल 2026 में एनसीआरबी द्वारा जारी 'क्राइम इन इंडिया 2024' की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में नाबालिगों के खिलाफ होनेवाले यौन शोषण के मामलों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है. साल 2024 में देश-भर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत कुल 69,191 मामले दर्ज किए गए. गंभीर यौन उत्पीड़न और पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के मामलों में 98 प्रतिशत पीड़ित लड़कियां थीं. पीड़ितों में सबसे बड़ी संख्या 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों की थी. इस श्रेणी में 23,000 से अधिक पीड़ित दर्ज किए गए. रिपोर्ट का सबसे चौंकानेवाला पहलू यह है कि 96.6 प्रतिशत मामलों में आरोपी नाबालिग के परिचित थे. इनमें दोस्त, ऑनलाइन दोस्त, पड़ोसी, पारिवारिक मित्र और रिश्तेदार शामिल हैं. बच्चों के खिलाफ हुए प्रत्येक 10 में से लगभग नौ साइबर अपराधों में बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री भेजना शामिल था. पॉक्सो कानून के तहत दर्ज नाबालिगों से बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश से दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है. हालांकि, हाल के वर्षों में रेप की रिपोर्ट करने की इच्छा बढ़ी है, क्योंकि रेप की कई घटनाओं ने मीडिया का ध्यान खींचा और लोगों में विरोध की भावना पैदा की. इस वजह से भारत सरकार को रेप और यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए अपने दंड कानून में सुधार करना पड़ा.

बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में साल 2012 में पॉक्सो कानून लाया गया. इस नए कानून में कई तरह के अपराधों का जिक्र है, जिनके लिए आरोपी को सजा दी जा सकती है. यह कानून 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा मानता है. इसमें बच्चे की शारीरिक उम्र को आधार माना गया है, लेकिन मानसिक उम्र पर कोई बात नहीं कही गई है. क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि रेप के लिए कौन जिम्मेदार है? यह उन सनकी लोगों की बीमार मानसिकता है जो सोशल मीडिया साइट्स पर पोर्नोग्राफी देखते हैं. लगातार पोर्न देखने से पुरुष महिलाओं के प्रति यौन रूप से आकर्षित होने लगते हैं. उनकी बीमार मानसिकता के कारण उनका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता. इसी वजह से वे नाबालिग लड़कियों और वयस्क महिलाओं, दोनों के साथ रेप की कोशिश करते हैं.

पूरे देश को झकझोर देनेवाले मामले

महाराष्ट्र के मथुरा रेप केस में एक आदिवासी किशोरी का कई पुलिसकर्मियों ने अपहरण कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषियों को बरी किए जाने पर देश-भर में हंगामा हुआ और इसी घटना के जरिये देश-भर के नारीवादी समूह पहली बार एकजुट हो पाए.

प. बंगाल से जुड़े एक मामले में 11 जनवरी 1994 को जस्टिस

शेष पृष्ठ-23 पर...

कारगिल से चंद्रयान तक
आत्मविश्वासी भारत की नई पहचान

कारगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर चंद्रमा की दक्षिणी सतह तक भारत की यात्रा केवल दूरी तय करने की कहानी नहीं है. यह उस राष्ट्र की कहानी है, जिसने संघर्षों के बीच आत्मविश्वास अर्जित किया, चुनौतियों को अवसर में बदला और दुनिया के सामने अपनी नई पहचान स्थापित की. एक ओर कारगिल की ऊंचाइयों पर भारतीय सैनिकों ने साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया तो दूसरी ओर भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की धरती पर तिरंगे की उपस्थिति दर्ज कराकर देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया.

भारत की यह यात्रा केवल सैन्य शक्ति या वैज्ञानिक उपलब्धि की कहानी नहीं है. यह बदलते भारत की कहानी है. यह उस राष्ट्र की कहानी है जिसने आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सामूहिक संकल्प के बल पर नई पहचान बनाई है.

वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है. दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भारतीय सैनिकों ने जिस साहस और पराक्रम का परिचय दिया, उसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया.

कारगिल की विजय केवल सैन्य सफलता नहीं थी. यह राष्ट्रीय आत्मविश्वास की विजय थी. देश ने देखा कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिक असंभव को संभव बना सकते हैं.

कारगिल ने भारत को यह सिखाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान और एकता का विषय भी है. उन वीर सैनिकों का बलिदान आज भी देशवासियों को राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है. प्रत्येक वर्ष मनाया जानेवाला कारगिल विजय दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए अनेक लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है.

> आज का भारत वैश्विक मंच पर नए आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश ने पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर तकनीकी, रणनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. यह बढ़ता हुआ आत्मविश्वास केवल सरकारी नीतियों में ही नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं और सोच में भी साफ दिखाई देता है.

कारगिल के लगभग ढाई दशक बाद भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया. चंद्रयान अभियान ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत केवल उपभोक्ता राष्ट्र नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नेतृत्व करनेवाला राष्ट्र बन रहा है.

डॉ. संतन कुमार राम

चंद्रयान-3 की सफलता केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी. यह करोड़ों भारतीयों के आत्मविश्वास की विजय थी. जब भारतीय अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रचा, तब यह उपलब्धि केवल वैज्ञानिकों की नहीं रही, बल्कि पूरे देश की उपलब्धि बन गई.

कारगिल और चंद्रयान दो अलग-अलग घटनाएं प्रतीत होती हैं, किंतु दोनों को जोड़नेवाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है- राष्ट्र का आत्मविश्वास. कारगिल ने यह सिद्ध किया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और चंद्रयान ने यह सिद्ध किया कि भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी वैश्विक नेतृत्व की क्षमता रखता है.

इक्कीसवीं सदी का भारत आत्मविश्वास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है. आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान, स्टार्टअप, नवाचार, रक्षा उत्पादन और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है. भारत की युवा शक्ति, वैज्ञानिक क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों ने विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है.

आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा भी इसी आत्मविश्वास का परिणाम है. देश अब केवल आयात पर निर्भर रहने के बजाय अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशी तकनीक पर बल दे रहा है. रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन, अंतरिक्ष मिशनों में आत्मनिर्भरता और डिजिटल क्षेत्र में

भारतीय नवाचार इसी परिवर्तन के संकेत हैं.

इस परिवर्तन में शिक्षा और युवा शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है. यदि यह युवा शक्ति ज्ञान, कौशल और नवाचार से सशक्त होगी तो भारत आनेवाले दशकों में विश्व नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है. कारगिल के वीर सैनिक और चंद्रयान के वैज्ञानिक, दोनों ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं.

आज का युवा सैनिक की तरह साहसी भी बनना चाहता है और वैज्ञानिक की तरह सृजनशील भी. वह सीमाओं की रक्षा भी करना चाहता है और अंतरिक्ष की सीमाओं को भी चुनौती देना चाहता है. यही नया भारत है, जहां राष्ट्रभक्ति और वैज्ञानिक सोच एक-दूसरे के पूरक बनकर सामने आती हैं.

भारत की नई राष्ट्रीय पहचान केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है. यह पहचान लोकतंत्र, विज्ञान, संस्कृति, शांति, विकास और मानवीय मूल्यों पर आधारित है. भारत विश्व को केवल तकनीक नहीं दे रहा, बल्कि सह-अस्तित्व, सहयोग और वैश्विक कल्याण का संदेश भी दे रहा है.

प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विकसित भारत-2047 के संकल्प में भी यही दृष्टि दिखाई देती है. आनेवाले वर्षों में भारत को आर्थिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से समावेशी राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा, अनुसंधान, विज्ञान, नवाचार और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना आवश्यक होगा.

कारगिल के वीरों ने हमें साहस का पाठ पढ़ाया. चंद्रयान के वैज्ञानिकों ने हमें सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा दी. दोनों घटनाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता रखता है.

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने युवाओं में राष्ट्रीय चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करें. शिक्षा संस्थानों को ऐसे नागरिक तैयार करने होंगे जो देश के प्रति समर्पित हों और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सक्षम हों.

अंततः, कहा जा सकता है कि कारगिल से चंद्रयान तक की यात्रा आत्मविश्वासी भारत की यात्रा है. यह यात्रा हमें बताती है कि साहस और विज्ञान, राष्ट्रभक्ति और नवाचार, परंपरा और आधुनिकता एक साथ आगे बढ़ सकते हैं. यही नए भारत की पहचान है.

कारगिल की चोटियों पर लहराता तिरंगा और चंद्रमा की धरती तक पहुंचा भारतीय स्वप्न, दोनों हमें एक ही संदेश देते हैं- यदि संकल्प मजबूत हो तो कोई ऊंचाई असंभव नहीं होती. यही आत्मविश्वास आज भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और यही उसकी नई पहचान भी. ■

...शेषांश पृष्ठ-13

अनियंत्रित पलायन भी कम होगा. विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब विकास का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा.

इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षकों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित होता है. शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा करनेवाले कर्मचारी नहीं होते, बल्कि वे भविष्य के नागरिकों के निर्माता होते हैं. वे विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ-साथ आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करते हैं.

नई शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है. अब शिक्षक केवल जानकारी देनेवाला व्यक्ति नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शक है. इसलिए, शिक्षक शिक्षा को भी समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होगा. डिजिटल दक्षता, नवाचार आधारित शिक्षण और कौशल उन्मुख शिक्षा भविष्य के शिक्षकों की अनिवार्य आवश्यकताएं बन चुकी हैं.

हालांकि, उपलब्धियों और संभावनाओं के बीच चुनौतियां भी कम नहीं हैं. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अवसरों की असमानता, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों की कमी, डिजिटल विभाजन, उद्योग और शिक्षा के बीच सीमित समन्वय तथा सामाजिक-आर्थिक विषमताएं आज भी हमारे सामने मौजूद हैं. कई बार प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी दक्षताओं और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतर बना रहता है. इस अंतर को कम करना आनेवाले वर्षों की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए.

वर्ष 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के एक सौ वर्ष पूर्ण करेगा, तब विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक सूचकांकों की वृद्धि से पूरा नहीं होगा. वास्तविक विकास तब होगा, जब प्रत्येक युवा को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिलेगा, जब प्रतिभा को संसाधनों की कमी रोक नहीं पाएगी, जब शिक्षा और कौशल समाज के हर वर्ग तक पहुंचेंगे और जब युवा अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त होंगे.

भारत की युवा शक्ति आज केवल भविष्य की आशा नहीं है, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत भी है. उसके पास ऊर्जा है, तकनीकी समझ है, नवाचार की क्षमता है और बेहतर भारत बनाने का संकल्प भी है. आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसे सही दिशा, उचित अवसर और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं. यदि ऐसा हुआ तो विकसित भारत-2047 कोई दूर का सपना नहीं रहेगा, बल्कि करोड़ों भारतीय युवाओं के परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प से निर्मित एक जीवंत वास्तविकता बन जाएगा.

निःसंदेह, कौशलयुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं. वे केवल राष्ट्र की प्रगति के सहभागी नहीं, बल्कि उसके भविष्य के निर्माता भी हैं. भारत की विकास यात्रा का अगला अध्याय उन्हीं के हाथों लिखा जाएगा और यही अध्याय आनेवाले समय में विश्व मंच पर भारत की नई पहचान गढ़ेगा. ■

भाजपा चाहती है कि हिंदू वोटर एकजुट रहें. सपा की चाहत है कि पिछड़े, दलित और मुसलमान एक मंच पर आएं. बसपा अपनी जमीनी पकड़ वापस पाने की कोशिश में है और कांग्रेस प्रियंका गांधी के चेहरे पर ब्राह्मण और महिला मतदाताओं को साधने में जुटी है.

नागेंद्र सिंह चौहान

गठबंधन और सोशल इंजीनियरिंग पर सबका भरोसा

• उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 •

विधानसभा चुनाव-2027 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की तैयारी तेज होती जा रही है. सर्वविदित है कि यहां बगैर जाति राजनीति की कल्पना नहीं हो सकती. जातिगत पैमाने पर देखें तो ठाकुर और ब्राह्मण जाति का बड़ा वर्ग भाजपा के साथ दिखता है. यादव और मुसलमान सपा के कोर वोटर हैं. दलित मतदाताओं में विभाजन नजर आता है. जाटव बसपा के साथ तो पासी और अन्य उपजातियां कभी इधर तो कभी उधर. कुर्मी, लोध, निषाद जैसे पिछड़े वर्ग चुनाव का रुख तय करते हैं. लेकिन, कोई भी दल अकेले बहुमत नहीं ला सकता. इसलिए, गठबंधन और सोशल इंजीनियरिंग ही यहां की राजनीति की कुंजी है.

जाति के आईने में राजनीतिक दल

यूपी में हर पार्टी अपनी कोर जाति को लेकर चलती है और साथ में कुछ और वर्गों को जोड़ने की कोशिश करती है. इसी जोड़-तोड़ पर 2027 की तैयारी भी टिकी है.

भाजपा अपनी सबसे बड़ी ताकत हिंदू वोट को एक छत के नीचे लाने की कोशिश में है. ठाकुर और ब्राह्मण पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं. शहरों का व्यापारी और मध्यम वर्ग भी साथ है. लेकिन, भाजपा यहीं नहीं रुकी है. पिछले चुनाव से गैर-यादव पिछड़े और गैर-जाटव दलितों पर खास मेहनत की गई है. कुर्मी, लोध, निषाद, मौर्य, पाल जैसी जातियों को टिकट और पद देकर पार्टी से जोड़ा गया है. साथ में आरएलडी के जरिये पश्चिम में जाट और निषाद पार्टी, अपना दल, सुभासपा के जरिये पूर्वांचल के मतदाताओं को भी साधा जा रहा है. भाजपा का संदेश साफ है कि हिंदू एक है और विकास सबका है. कानून-व्यवस्था और मंदिर के मुद्दे इस समीकरण को बांधने का काम करते हैं.

सपा की राजनीति की धुरी हमेशा से यादव और मुस्लिम रहे हैं. लेकिन, अखिलेश यादव जानते हैं कि अकेले इनसे सरकार नहीं बनेगी. इसलिए, उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला दिया- पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक. इसका मतलब है यादव के साथ कुर्मी, लोध, तेली, नाई जैसी पिछड़ी जातियों को जोड़ना. दलित में जाटव के अलावा पासी, खटीक, धोबी को साधना और मुस्लिम वोट को एकमुश्त अपने पाले में रखना. पार्टी का टारगेट है कि भाजपा से नाराज पिछड़े और दलित उसके साथ आएं.

बसपा की पहचान हमेशा से दलित, खासकर जाटव वोट से रही है. मायावती के समय में यह वोट एकमुश्त बसपा के साथ जाता था. लेकिन, पिछले कुछ साल में यह बिखरा है. अब बसपा की कोशिश है कि जाटव जाति को फिर से एकजुट किया जाए और साथ में गैर-जाटव दलित उपजातियों को भी वापस लाया जाए. साथ ही, पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को भी टटोल रही है जो सपा से नाराज है.

कांग्रेस का कोई एक कोर वोट बैंक नहीं बचा है. इसलिए, पार्टी ब्राह्मण और दूसरे सवर्ण मतदाताओं की वापसी की कोशिश कर रही है. कांग्रेस प्रियंका गांधी के जरिये महिलाओं को साधने में जुटी है. पार्टी किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दे भी उठा रही है. कांग्रेस जानती है कि वह अकेले सरकार नहीं बना सकती, इसलिए पार्टी गठबंधन की राह देख रही है. उसका खेल यह है कि अगर 40-50 सीटें भी आ गईं तो वह किंगमेकर बन जाएगी.

आरएलडी पश्चिमी यूपी की पार्टी है. जाट उसके कोर वोटर हैं. जयंत चौधरी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर अपनी जमीन बचाई है. वह गुर्जर और कुछ किसान जातियों को भी साथ लेकर चल रहे हैं. आरएलडी के लिए 2027 में सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि

किसान आंदोलन के बाद जाट वोट बैंक उसके साथ कितना रहता है.

छोटे दल भी अपने हिसाब से खेल रहे हैं. निषाद पार्टी निषाद और मल्लाह वोट पर पकड़ रखती है. अपना दल के पास कुर्मी वोटरों का बड़ा हिस्सा है. सुभासपा राजभर वोट पर दावा करती है. चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी युवा दलित वर्ग में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है. ये दल 10-15 सीटें इधर-से-उधर कर सकते हैं.

बहुमत के लिए चाहिए 202 सीटें

आसन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतना चाहती है. पार्टी के पास 2022 में 255 सीटें थीं और 57 सीटें घटी थीं. अब वह कह रही है कि कानून-व्यवस्था और विकास के काम से नुकसान की भरपाई होगी. योगी फैक्टर और डबल इंजन को भुनाकर भाजपा 2017 के आंकड़े 312 के आसपास पहुंचना चाहती है.

सपा का लक्ष्य 150 से 175 सीटों का है. पिछले चुनाव में पार्टी को 111 सीटें मिली थीं और 64 सीटें बढ़ी थीं. अखिलेश का फोकस पीडीए फॉर्मूले पर है. लोकसभा चुनाव-2024 में सपा ने 37 सीटें जीतीं जो यूपी में सबसे ज्यादा थीं. अखिलेश यादव इसी लहर को विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहते हैं.

बसपा का लक्ष्य कम-से-कम 50 सीटें हासिल करना है. पार्टी 2022 में सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई. मायावती की कोशिश है कि दलित वोट फिर से एकजुट हो और मुस्लिम वोट का कुछ हिस्सा वापस आए.

कांग्रेस का लक्ष्य 50 से ज्यादा सीटों पर जीत का है. पार्टी को 2022 में सिर्फ 2 सीटें मिलीं. प्रियंका गांधी महिला, किसान और युवा वर्ग से जुड़े मुद्दों पर फोकस कर रही हैं. कांग्रेस को पता है कि अकेले सरकार नहीं बनेगी, इसलिए वह किंगमेकर बनना चाहती है.

आरएलडी का लक्ष्य 15 से 20 सीटों का है. पार्टी ने 2022 में 8 सीटें जीती थीं. पश्चिम में जाट और किसान मतदाताओं को साधकर वह भाजपा के साथ गठबंधन में अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है. लोकसभा चुनाव-2024 में आरएलडी ने 2 सीटें जीतीं.

छोटे सहयोगी दल- अपना दल, निषाद पार्टी, सुभासपा सब अपनी मौजूदा सीटें बचाकर 2-3 सीटें और बढ़ाना चाहते हैं. अपना दल के पास 12, निषाद पार्टी के पास 6 और सुभासपा के पास 6 सीटें हैं.

विधानसभा चुनाव-2027 का फैसला इसी बात पर होगा कि कौन किसको कितना जोड़ पाता है. अगर, भाजपा गैर-यादव पिछड़े और गैर-जाटव दलित को अपने साथ रख पाई तो वह मजबूत रहेगी. अगर, सपा पीडीए को जमीन पर उतार पाई तो मुकाबला कांटे का होगा. अगर, बसपा अपने पुराने दलित वोटरों को वापस ले आई तो त्रिकोणीय लड़ाई बन जाएगी. ■

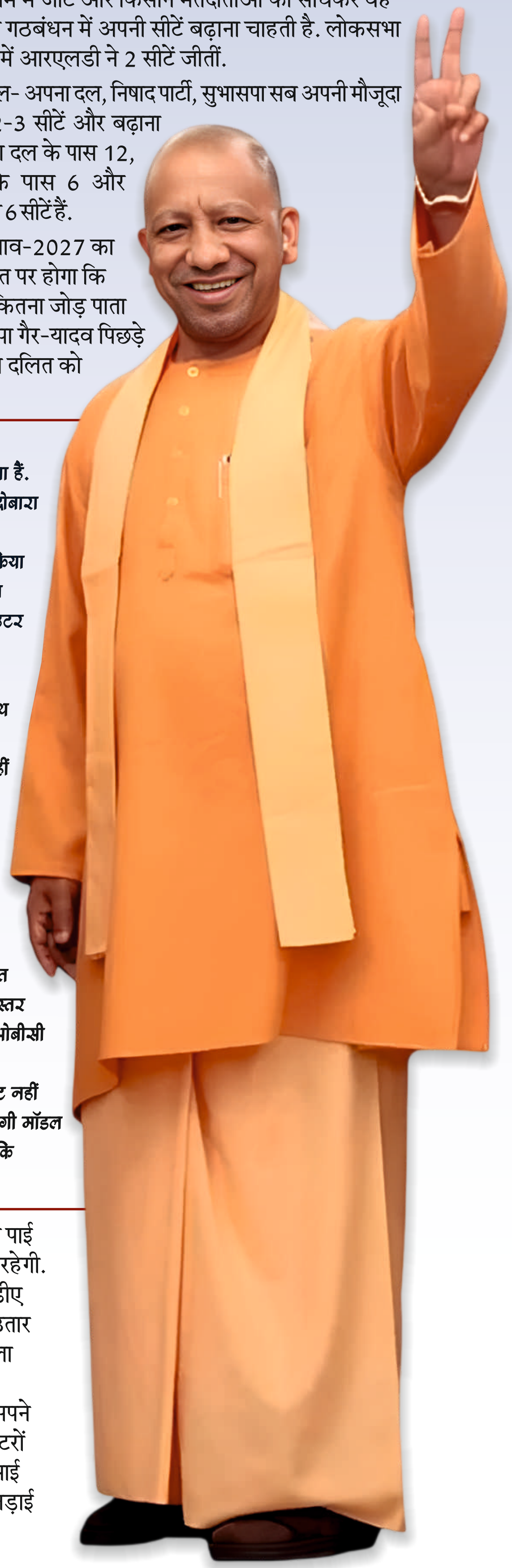

यूपी की राजनीति की धुरी हैं योगी

योगी आदित्यनाथ आज यूपी की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे और नैरेटिव सेट करनेवाले नेता हैं. वह भाजपा के अंदर निर्विवाद नेता हैं. योगी 2017 से मुख्यमंत्री हैं. वह साल 2022 में भी दोबारा पूर्ण बहुमत से आए. यूपी में अब 'योगी ब्रांड' खुद एक चुनावी हथियार बन गया है.

'बुलडोजर मॉडल' और 'जीरो टॉलरेंस' अब भाजपा की पहचान है. योगी से पहले यूपी गुंडा और माफिया राज का पर्याय था. योगी सरकार ने इसे बदलकर 'इन्वेस्टर फ्रेंडली यूपी' का नैरेटिव बनाया. माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई को जनता 'कठोर फैसला' मानती है. पुलिस एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पर अगर कुछ विरोध है तो समर्थन भी काफी है. उद्योग, फिल्म सिटी एवं एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट का क्रेडिट भी उन्हें मिलता है.

गोरक्षपीठाधीश्वर होने के कारण योगी का हिंदुत्व चेहरा सबसे मजबूत है. राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर योगी फ्रंटलाइन पर रहते हैं. सनातन, लव जिहाद कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून- इन मुद्दों से भाजपा के कोर वोटर को ऊर्जा मिलती है. विपक्ष भी अब इन्हीं मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर है.

योगी ने विकास और ब्रांडिंग के दम पर उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाने का नैरेटिव सेट कर दिया है. उन्होंने पूर्वांचल, बुंदेलखंड एवं गंगा एक्सप्रेसवे बनवाकर 'एक्सप्रेसवे वाले बाबा' की छवि भी बना ली है. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर आदि की चर्चा हो रही है. भाजपा यूपी में योगी के नेतृत्व में विकास और सुरक्षा के समीकरण पर भरोसा कर रही है.

आज स्थिति यह है कि सपा, बसपा और कांग्रेस को अब योगी को केंद्र में रखकर ही रणनीति बनानी पड़ती है. सपा पीडीए फॉर्मूले से जातीय गोलबंदी कर योगी के हिंदुत्व और विकास की रणनीति को मात देने की कोशिश कर रही है. योगी की लोकप्रियता की राह में कुछ चुनौतियां भी हैं. विधायक एवं मंत्री स्तर पर भ्रष्टाचार और दबंगई की शिकायतें आती हैं. युवा वोटर रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा मानता है. ओबीसी और दलित वोटरों को अभी और साधना है. कुछ मामलों में सवर्ण भी मन-ही-मन नाराज हैं.

लोकसभा चुनाव-2024 में भाजपा को सीटें कम मिली थीं, पर योगी की लोकप्रियता रेटिंग में गिरावट नहीं आई है. विधानसभा चुनाव-2027 योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा. अगर, भाजपा जीती तो इसे योगी मॉडल की जीत कहा जाएगा और अगर हारी तो योगी फैक्टर को फेल माना जाएगा. इसलिए, कह सकते हैं कि फिलहाल यूपी की राजनीति की धुरी योगी आदित्यनाथ ही हैं.

प. बंगाल

पुनर्वास की चुनौती

स्टेशन से सड़क पर हॉकर

रेलवे स्टेशनों और पटरियों के आसपास अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत हावड़ा, जादवपुर, दमदम और पार्क सर्कस जैसे प्रमुख स्टेशनों से अवैध रूप से दुकानें चला रहे सैकड़ों हॉकरों को हटाया गया है. इस कार्रवाई से यात्रियों को आवागमन में सुविधा तो मिली है, लेकिन गरीब दुकानदारों की आजीविका प्रभावित होने के कारण जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बवाल भी देखने में आया है.

भारतीय रेल विश्व का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. प्रतिदिन 2.3 से 2.5 करोड़ यात्री रेल सेवाओं का उपयोग करते हैं. भारतीय रेल के लिए प. बंगाल एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है, जहां हर दिन लाखों लोग नौकरी, पढ़ाई, व्यापार और दूसरे कामों के लिए रेलवे का इस्तेमाल करते हैं. कोलकाता, सियालदह, हावड़ा, आसनसोल, बर्दवान, खड़गपुर, मालदा एवं न्यू जलपाईगुड़ी समेत कई बड़े रेलवे स्टेशन हर दिन बड़ी संख्या में यात्रियों का दबाव झेलते हैं. इन स्टेशनों पर लंबे समय से बड़ी तादाद में फेरीवालों और अवैध दुकानों का दिखना एक आम बात रही है. ये पानी, चाय-कॉफी, फल, खाना, किताब-अखबार एवं खिलौने जैसी कई जरूरी चीजें बेचते हैं. हॉकर यात्रियों को तुरंत सुविधा तो देते हैं, लेकिन इनकी अनियंत्रित संख्या आने-जाने में परेशानी पैदा करने के साथ स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को भी अक्सर चुनौती पेश करती रहती है.

अनन्या समद्दार

इसी के मद्देनजर प. बंगाल में भाजपा की नवनिर्वाचित राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशनों और पटरियों के आसपास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. इस कदम के परिणामस्वरूप यात्रियों के लिए सुविधा और सुरक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन हजारों गरीब परिवारों के समक्ष जीवन निर्वहन एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया है. फेरीवाले रेलवे स्टेशनों की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और यात्री सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वे कम पूंजी में अपना व्यवसाय चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. दूसरी ओर, रेलवे प्रशासन का यह भी दायित्व है कि स्टेशन परिसर सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित रहे.

प. बंगाल में लंबे समय से हॉकरों ने बगैर अनुमति बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज और प्रवेश-निकास मार्गों पर कब्जा कर रखा था, जिससे यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी. इसके विपरीत एक सच्चाई यह भी थी कि वे यात्रियों को कम कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रहे थे. कई बार देर रात या आपातकालीन परिस्थितियों में ये फेरीवाले यात्रियों की सहायता भी किया करते थे. विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्ग के लोग इनसे ही सस्ते सामान खरीदते थे. इस तरह, हॉकर केवल असुविधा का एक कारण नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण अंग भी हैं.

हालांकि, रेलवे प्रशासन और नवनिर्वाचित भाजपा की राज्य सरकार द्वारा फेरीवालों को हटाने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं जैसे- स्टेशन परिसर में अतिक्रमण समाप्त करना, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, भीड़भाड़ को कम करना, प्लेटफॉर्म को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाना, दुर्घटनाओं की संभावना कम करना, रेलवे की आधिकारिक दुकानों और लाइसेंसधारी विक्रेताओं को बढ़ावा देना और आधुनिक रेलवे स्टेशन विकसित करना. ये विषय केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. इन्हें ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार ने रेलवे परिसरों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाना शुरू कर दिया है. इस अभियान के शुरू होते ही समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच

इसकी चर्चा जोरों पर है. उच्च वर्ग के लोगों के अनुसार, ये आधुनिक शहरीकरण की ओर एक प्रधान कदम है, जबकि मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग इसके अच्छे और बुरे, दोनों पहलुओं पर विचार कर रहे हैं. व्यापारी वर्ग भी इस विषय पर दो भागों में विभाजित होता दिख रहा है, जिसके एक हिस्से में रेलवे की आधिकारिक दुकानें और लाइसेंसधारी विक्रेता हैं जो इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर छोटे व्यापारी और वे हॉकर हैं जो अब तक रेलवे स्टेशन और उससे संलग्न परिसर में व्यापार कर अपना जीवन निर्वहन कर रहे थे, पर इस अतिक्रमण विरोधी अभियान के फलस्वरूप वर्तमान समय उनके लिए किसी आपदा से कम नहीं. कुल मिलाकर इस अभियान के सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों ही प्रभाव विचारणीय हैं.

इसके सकारात्मक प्रभावों पर विचार किया जाए तो जब प्लेटफॉर्म पर अनधिकृत हॉकरों की संख्या अधिक होती है, तब यात्रियों के चलने-फिरने में कठिनाई होती है. आपातकालीन स्थिति में निकासी भी बाधित होती है. इनके हटने से यात्रियों की सुरक्षा बेहतर होगी और प्लेटफॉर्म अधिक खुला और व्यवस्थित होगा, जिससे यात्रियों को आने-जाने में सुविधा होगी. खाद्य पदार्थ बेचनेवाले फेरीवालों द्वारा

उत्पन्न कचरे के कारण स्टेशन गंदे हो जाते हैं, उनके हटने से सफाई व्यवस्था बेहतर होगी. कई बार यात्री सामान खरीदते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. भीड़ कम होने से ऐसी दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है. रेलवे द्वारा लाइसेंस प्राप्त दुकानदार नियमों के अनुसार व्यवसाय करते हैं. अनधिकृत हॉकरों के हटने से उन्हें उचित व्यापारिक अवसर मिलेगा. सरकार रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रही है. व्यवस्थित प्लेटफॉर्म, बेहतर यात्री सुविधाएं और साफ-सुथरा वातावरण इस प्रक्रिया को सफल बनाते हैं. इस अतिक्रमण विरोधी अभियान का सकारात्मक प्रभाव अपराध नियंत्रण पर भी पड़ेगा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन परिसर की अवैध दुकानों को अक्सर रात के समय असामाजिक गतिविधियों के अड्डों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें अब खाली करा लिया गया है. कम भीड़ होने पर सुरक्षा एजेंसियों को निगरानी करने में सुविधा होती है.

इस अभियान का सबसे नकारात्मक प्रभाव हजारों गरीब परिवारों की आजीविका पर पड़ा है. अनेक फेरीवाले वर्षों से इसी व्यवसाय पर निर्भर थे, आज अचानक उनके पास कोई रोजगार नहीं है. आय रुक जाने से ऐसे परिवार आर्थिक संकट में आ गए हैं. इनके लिए बच्चों की पढ़ाई, भोजन और स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना भी अत्यंत कठिन हो गया है. इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ लोग मजबूरी में गलत रास्तों की ओर भी जा रहे हैं. दूसरी ओर, यात्रियों को तुरंत सुविधाएं उपलब्ध कराने में हॉकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनके हटने के बाद कई छोटे स्टेशनों पर यह सुविधा भी सीमित हो गई है. साथ ही, एक अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि फेरीवाले स्थानीय किसानों और थोक बाजारों से सामान खरीदकर ही अपना व्यवसाय चलाते थे. कई हॉकर वृद्ध, महिलाएं या आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, उन्हें इस तरह हटाना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता.

दरअसल, केवल फेरीवालों को हटाना ही समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. इसके लिए प्रशासन और सरकार को ऐसा मॉडल अपनाना चाहिए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा भी कायम रहे और गरीब लोगों की आजीविका भी सुरक्षित रहे. पटरियों के किनारे अवैध झुग्गियों के टूट जाने से कई परिवार बेघर हो गए हैं, जिससे उनके सामने रहने का बड़ा संकट पैदा हो गया है. श्रमिक संगठनों और विपक्षी दलों का आरोप है कि उचित पुनर्वास एवं वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किए बिना ही सरकार द्वारा आधी रात को अचानक बुलडोजर चलाकर बेदखली की जा रही है. इस अभियान के कारण स्थानीय स्तर पर हिंसक झड़पें, चक्का जाम, पीड़ितों द्वारा रेलवे की पटरियों पर प्रदर्शन और पुलिस-जनता के बीच टकराव की स्थिति भी कई जगहों पर देखी गई. इन तीव्र विध्वंस अभियानों और इनके परिणामों को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया है और कुछ मामलों में स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.

ऐसे में सरकार का यह दायित्व है कि वह विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखे. यदि रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है तो प्रभावित लोगों के पुनर्वास की भी समान रूप से जिम्मेदारी सरकार की ही होनी चाहिए. गरीब लोगों के हितों की रक्षा करते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करना ही सुशासन का परिचायक है. इसलिए, केवल निष्कासन की नीति ही पर्याप्त नहीं है. उचित समाधान यही है कि रेलवे प्रशासन और सरकार सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखते हुए योग्य हॉकरों का पंजीकरण करे, उन्हें निर्धारित स्थान उपलब्ध कराए तथा जिनका व्यवसाय प्रभावित हो, उनके लिए पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करे. साथ ही, आम नागरिकों का भी यह दायित्व बनता है कि वे इस अभियान को सफल बनाने में सरकार और रेलवे प्रशासन का यथासंभव सहयोग करें. विकास तभी सार्थक माना जाएगा, जब वह समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करे. अतः, आधुनिक रेलवे व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन स्थापित करना ही इस समस्या का सबसे उचित और टिकाऊ समाधान है. ■

स्वास्थ्य सेवा
संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व

एक संवेदनशील डॉक्टर मरीज को केवल शारीरिक राहत ही नहीं, बल्कि जीने का विश्वास और संबल भी देता है. मधुर व्यवहार, चिकित्सक के सांत्वना–भरे शब्द और आत्मीय बोल कई बार मरीज के कष्ट और तनाव को वैसे ही कम कर देते हैं. कर्तव्यनिष्ठा और त्याग एवं विपरीत परिस्थितियों, आपदाओं या महामारियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा, इस पेशे की सच्ची संवेदना के प्रमाण हैं.

रात के दो बजे हैं. अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में अचानक एक गंभीर मरीज लाया जाता है. परिजनों की आंखों में भय है, चेहरे पर चिंता है और मन में एक ही उम्मीद- डॉक्टर. कुछ ही क्षणों में चिकित्सक अपनी थकान, निजी जीवन और समय की सीमाओं को पीछे छोड़कर उपचार में जुट जाता है. यह दृश्य किसी एक अस्पताल या एक शहर का नहीं है. भारत के हजारों अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन ऐसी असंख्य कहानियां जन्म लेती हैं. इन कहानियों के केंद्र में होते हैं चिकित्सक जो केवल रोगों का उपचार नहीं करते, बल्कि जीवन को बचाने और आशा को जीवित रखने का कार्य भी करते हैं.

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हमें ऐसे ही समर्पित चिकित्सकों के योगदान को स्मरण करने और सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है. भारत में यह दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को महान चिकित्सक, शिक्षाविद् और समाजसेवी डॉ. बिधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है. उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि चिकित्सा केवल विज्ञान नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम है. आज जब स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर विकसित हो रही हैं और समाज नई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब चिकित्सकों की भूमिका पहले से कहीं अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण हो गई है.

डॉ. शारिक हुसैन

स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होता है. आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और मानवीय कल्याण का सीधा संबंध नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है. एक स्वस्थ समाज ही उत्पादक, रचनात्मक और प्रगतिशील समाज बन सकता है. इसी कारण स्वास्थ्य सेवा को केवल उपचार की व्यवस्था नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है. इस व्यवस्था की धुरी चिकित्सक होते हैं जिनके ज्ञान, अनुभव और निर्णय पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर करता है.

पिछले कुछ दशकों में चिकित्सा विज्ञान ने अभूतपूर्व प्रगति की है. आधुनिक तकनीकों ने रोगों की पहचान और उपचार की संभावनाओं को विस्तृत किया है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक सर्जरी, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और उन्नत निदान प्रणालियों ने चिकित्सा जगत को नई दिशा दी है. लेकिन, तकनीक की इस तेज रफ्तार दुनिया में भी एक तत्व ऐसा है, जिसकी जगह कोई मशीन नहीं ले सकती- मानवीय संवेदना. एक चिकित्सक का व्यवहार, उसकी सहानुभूति, उसका धैर्य और रोगी के प्रति उसका मानवीय दृष्टिकोण उपचार प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है.

भारतीय समाज में डॉक्टर को लंबे समय से विश्वास और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है. जब कोई व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना या जीवन के संकटपूर्ण क्षणों से गुजरता है, तब उसकी सबसे बड़ी आशा चिकित्सक ही होता है. अस्पताल की दहलीज पर पहुंचते ही रोगी अपना भय, अपनी पीड़ा और अपनी उम्मीदें डॉक्टर के हाथों में सौंप देता है. यही विश्वास चिकित्सा पेशे की सबसे बड़ी पूंजी है और इसी विश्वास को बनाए रखना चिकित्सा समुदाय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है.

कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को यह एहसास कराया कि चिकित्सक केवल उपचारकर्ता नहीं, बल्कि समाज के वास्तविक संरक्षक हैं. महामारी के कठिन दिनों में जब लोग अपने घरों में सुरक्षित रहने का प्रयास कर रहे थे, तब डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालों में दिन-रात सेवा में लगे हुए थे. अनेक चिकित्सकों ने व्यक्तिगत जोखिम उठाकर मरीजों का उपचार किया. कई ने अपने परिवारों से दूरी बनाई और कई ने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया. महामारी ने चिकित्सा पेशे के भीतर निहित सेवा, त्याग और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया.

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियां भी कम नहीं हैं. एक ओर महानगरों में अत्याधुनिक अस्पताल हैं तो दूसरी ओर ऐसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अभी भी सीमित है. इन परिस्थितियों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है. वे सीमित संसाधनों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं. अक्सर उनका योगदान सार्वजनिक विमर्श में कम दिखाई देता है, जबकि वास्तव में वे देश की स्वास्थ्य सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं.

आज भारत एक नए स्वास्थ्य संक्रमण के दौर से गुजर रहा है. संक्रामक रोगों की चुनौतियां अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं, वहीं

दूसरी ओर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. बदलती जीवनशैली, शहरीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण और तनाव ने स्वास्थ्य संबंधी नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं. ऐसे समय में चिकित्सकों की भूमिका केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं रह सकती. उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता, रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवनशैली के प्रसार में भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी.

मानसिक स्वास्थ्य आज भारतीय समाज के सामने उभरती हुई एक गंभीर चुनौती है. प्रतिस्पर्धा, सामाजिक दबाव, आर्थिक असुरक्षा और डिजिटल जीवनशैली ने मानसिक तनाव को बढ़ाया है. दुर्भाग्यवश मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभी भी सीमित है. ऐसे में चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जिम्मेदारी केवल उपचार प्रदान करना नहीं, बल्कि समाज को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाना भी है.

चिकित्सकों को आत्ममंथन करना चाहिए. चिकित्सा सेवा का मूल उद्देश्य केवल रोगों का उपचार नहीं, बल्कि मानव जीवन की गरिमा की रक्षा करना है. एक आदर्श चिकित्सक अपने ज्ञान के साथ-साथ करुणा, संवेदना और नैतिक मूल्यों का भी वाहक होता है. यही गुण उसे समाज में विशेष सम्मान दिलाते हैं.

विकसित भारत-2047 की परिकल्पना में स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका केंद्रीय है. यदि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करनी होगी जो आधुनिक, समावेशी, सुलभ और मानवीय हो. इस लक्ष्य की प्राप्ति में चिकित्सकों की भूमिका केवल पेशेवर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व निभाने की भी है. वे स्वस्थ भारत के निर्माता हैं और उनके योगदान के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा.

हमें उन सभी चिकित्सकों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए जो अपने ज्ञान, समर्पण और संवेदनशीलता के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहे हैं. वे केवल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि विश्वास के संरक्षक, जीवन के रक्षक और सामाजिक उत्तरदायित्व के जीवंत प्रतीक हैं. उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना वास्तव में एक स्वस्थ, संवेदनशील और मानवीय समाज के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है. ■

...शेषांश पृष्ठ-15

आनंद ने सुरक्षा गार्ड धनंजय चटर्जी की मौत की सजा को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया. चटर्जी ने 1990 में कोलकाता के एक अपार्टमेंट में स्कूल जानेवाली एक लड़की का रेप और मर्डर किया था.

दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 10 मई 2017 को एक 40 साल के आदमी ने पड़ोस में रहनेवाली 21 महीने की बच्ची का रेप किया. वह आदमी बच्ची के पिता का परिचित था और अक्सर उसे बच्ची के साथ खेलने दिया जाता था. लेकिन, उस दिन बच्ची को अकेला पाकर उस आदमी ने घंटों तक उसका रेप किया, जब तक कि उसके पिता घर नहीं लौट आए. बच्ची को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर थी.

एक और घटना 10 मई 2017 को हुई, जिसमें वाराणसी में एक 24 साल के आदमी ने 5 साल की मूक-बधिर (बोलने और सुनने में असमर्थ) बच्ची का रेप किया.

कठुआ रेप केस (2018), जिसमें कठुआ के एक मंदिर में आठ अलग-अलग लोगों ने आठ साल की बच्ची के साथ बेरहमी से गैंगरेप किया. बताया जाता है कि उसे कई दिनों तक मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया और रेप किया गया. ऐसा लगता है कि यह उस समुदाय के बाकी सदस्यों को इलाके से भगाने की कोशिश थी.

एक और मामला- जींद रेप केस (2018), जिसमें हरियाणा के जींद की एक 15 साल की लड़की जो तीन दिनों से लापता थी, का शव झांसा गांव में मिला. मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उसके साथ बेरहमी से गैंगरेप किया गया था और उसके निजी अंगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया था.

हरियाणा के पानीपत शहर में एक नाबालिग के साथ रेप की भयानक घटना हुई, जहां 11 साल की बच्ची का उसके दो पड़ोसियों ने रेप किया और हत्या कर दी. कहा जाता है कि हत्या के बाद उन्होंने उसके शव के साथ भी घिनौनी हरकत (नेक्रोफिलिया) की.

एक चौंकानेवाली घटना में 16 फरवरी 2020 की शाम को कथित तौर पर पांच महीने की बच्ची का उसके चचेरे भाई ने रेप किया. बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

हरियाणा के जींद जिले में 24 अप्रैल 2020 की शाम को एक 14 साल की लड़की का कथित तौर पर तीन युवकों ने रेप किया, जिनमें एक 16 साल का लड़का भी शामिल था. वे उसे बहला-फुसलाकर उसके घर के पास एक गांव के स्कूल की बिल्डिंग में ले गए थे. पुलिस ने बताया कि लड़की को लड़का जानता था और किसी बहाने से उसे ले गया था. आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत रेप का मामला दर्ज किया गया.

क्या यह उस देश के लिए शर्म की बात नहीं है, जहां स्कूल जानेवाली लड़कियों और नाबालिगों का रेप होता है और उन्हें न्याय नहीं मिलता? क्या लड़कियां या महिलाएं सिर्फ सेक्स की चीज हैं? क्या किसी भी उम्र के आदमी को किसी महिला का रेप करने का हक मिल जाता है? चाहे वह 5 साल की बच्ची हो, 23 साल की युवती हो या 50 साल की महिला, रेप तो रेप ही होता है.

रेप से न सिर्फ लड़की का शरीर टूट जाता है, बल्कि उसका मन भी टूट जाता है. हम सोच भी नहीं सकते कि जब बिना मर्जी के कोई आदमी किसी छोटी बच्ची या महिला के शरीर को छूता है तो उसे कैसा महसूस होता है. क्या समाज कभी उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करता है जो रेप के दौरान सहना पड़ता है? सड़कों पर हाथों में प्लेकार्ड लेकर चिल्लाना रेप पीड़िता के लिए न्याय की लड़ाई नहीं है. कोर्ट से न्याय मिलने का इंतजार किए बिना रेप करनेवालों को वहीं गोली मार देनी चाहिए या खत्म कर देना चाहिए. दुर्योधन और दुःशासन तो सदियों पहले ही इस दुनिया से चले गए थे. अफसोस की बात है कि आज भी हमारे समाज में अनगिनत दुर्योधन और दुःशासन बुरी नजर और हवस-भरी सोच के साथ घूम रहे हैं. ये आपके दोस्त, दोस्त के दोस्त, कजिन, चाचा, रिश्तेदार या अनजान लोग भी हो सकते हैं. रेप करनेवालों की यह लिस्ट बहुत लंबी है.

क्या महिलाओं को कभी उस अन्याय के लिए न्याय मिल पाएगा जो पुरुष उनके मन और शरीर के साथ करते हैं? अफसोस, हमारे देश में इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है. ■

जिज्ञासा से उत्कृष्टता तक

शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति

जब दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल क्रांति और तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है, तब एक प्रश्न पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है- क्या शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन है या यह मनुष्य के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानकर उसे उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचानेवाली परिवर्तनकारी शक्ति भी है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मानव सभ्यता की उस लंबी यात्रा में मिलता है, जिसकी शुरुआत जिज्ञासा से होती है और जिसका अंतिम लक्ष्य ज्ञान, विवेक तथा उत्कृष्टता की प्राप्ति है.

मानव इतिहास पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि सभ्यता का विकास किसी संयोग का परिणाम नहीं था. इसके पीछे मनुष्य की जानने, समझने और खोज करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है. जब आदिम मानव ने आकाश की ओर देखा होगा, जब उसने पहली बार आग की शक्ति को पहचाना होगा या जब उसने प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास किया होगा, तभी ज्ञान की पहली किरण फूटी होगी. वस्तुतः, जिज्ञासा ही वह शक्ति है, जिसने मनुष्य को अन्य जीवों से अलग पहचान दी और उसे निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया.

बचपन जिज्ञासा का सबसे सुंदर रूप है. एक छोटा बच्चा अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना चाहता है. वह बार-बार प्रश्न पूछता है. उसके लिए दुनिया एक रहस्य है और वह उस रहस्य को समझने के लिए उत्सुक रहता है. यही उत्सुकता शिक्षा की पहली पाठशाला है. दुर्भाग्यवश अनेक बार हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों की इसी स्वाभाविक जिज्ञासा को पर्याप्त पोषण नहीं दे पाती. प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और उत्तर याद करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है. परिणामस्वरूप, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की खोज से हटकर परीक्षा में सफलता तक सीमित हो जाता है.

वास्तविक शिक्षा इससे कहीं व्यापक है. शिक्षा केवल तथ्यों और सूचनाओं का संग्रह नहीं है. यह मनुष्य को सोचने की क्षमता देती है. उसे सही और गलत के बीच अंतर समझना सिखाती है. यह दृष्टिकोण का विस्तार करती है और व्यक्ति को स्वयं तथा समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है. यही कारण है कि शिक्षा को किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति माना जाता है.

> एक ऐसी ताकत जो न केवल व्यक्तियों के जीवन को बदल देती है, बल्कि संपूर्ण समाज और राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करती है, वह है- शिक्षा. यह केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि सशक्तीकरण, सामाजिक उत्थान और समग्र विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है.

डॉ. अबसारुल हक

भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक परंपरा में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है. हमारे प्राचीन ग्रंथ संवाद, तर्क और जिज्ञासा की समृद्ध परंपरा के साक्षी हैं. उपनिषदों में शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु उत्तर देता है. यह प्रक्रिया केवल धार्मिक या दार्शनिक विमर्श नहीं, बल्कि ज्ञान की खोज की उत्कृष्ट पद्धति थी. नचिकेता, गार्गी और याज्ञवल्क्य जैसे पात्र हमें बताते हैं कि प्रश्न पूछना भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल स्वभाव रहा है. यही परंपरा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ज्ञान का विकास वहीं संभव है, जहां प्रश्नों का सम्मान होता है.

आज का युग ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का युग है. दुनिया-भर में प्रतिस्पर्धा के नए मानदंड स्थापित हो रहे हैं. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और डिजिटल तकनीक ने कार्य और जीवन, दोनों के स्वरूप को बदल दिया है. ऐसे समय में केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं है. जानकारी तो एक मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उपलब्ध है. आवश्यकता उस क्षमता की है जो जानकारी को ज्ञान में और ज्ञान को बुद्धिमत्ता में परिवर्तित कर सके. यही कार्य शिक्षा करती है.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में शिक्षा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है. तकनीक उत्तर दे सकती है, लेकिन प्रश्न नहीं बना सकती.

मशीनें सूचना उपलब्ध करा सकती हैं लेकिन संवेदनशीलता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का निर्माण नहीं कर सकतीं. यह कार्य केवल शिक्षा ही कर सकती है. यदि तकनीक गति प्रदान करती है तो शिक्षा दिशा प्रदान करती है. दिशा के बिना गति अनेक बार भ्रम और संकट का कारण बन जाती है.

शिक्षा की वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती है, जब वह व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है. भारत के अनेक गांवों और कस्बों में ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं, जहां शिक्षा ने पीढ़ियों की नियति बदल दी. सीमित संसाधनों वाले परिवारों के बच्चे शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक, शिक्षक, चिकित्सक, प्रशासक और उद्यमी बने. उन्होंने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा दी. यही शिक्षा का सबसे बड़ा चमत्कार है.

बिहार जैसे राज्यों का अनुभव भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है. पिछले वर्षों में शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं. विद्यालयों का विस्तार हुआ है, छात्राओं की भागीदारी बढ़ी है और उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार हुआ है. फिर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में अभी लंबी दूरी तय करनी है. केवल विद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा. आवश्यकता ऐसी शिक्षा व्यवस्था की है जो विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता का विकास कर सके.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. यह नीति रटने की संस्कृति से हटकर समझ, विश्लेषण, अनुभवात्मक अधिगम और नवाचार पर बल देती है. इसका उद्देश्य ऐसे शिक्षार्थियों का निर्माण करना है जो केवल जानकारी ग्रहण करनेवाले न हों, बल्कि ज्ञान का सृजन करनेवाले बनें. बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान और लचीले पाठ्यक्रम की अवधारणा इसी सोच का परिणाम है.

शिक्षा की इस परिवर्तनकारी यात्रा में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा नहीं करता, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानता है. वह उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है. वह असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने का साहस देता है. वह विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, निरंतर सीखनेवाला व्यक्ति अपने लिए नई संभावनाएं निर्मित कर सकता है. दरअसल, शिक्षक केवल ज्ञान का प्रदाता नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माता होता है. उसके शब्द, उसका व्यवहार और उसकी प्रेरणा विद्यार्थियों के जीवन पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं. जिस समाज में शिक्षक का सम्मान होता है, वहां ज्ञान और नवाचार की संस्कृति विकसित होती है. इसलिए, यदि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है तो शिक्षक को केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में देखना होगा.

हालांकि, उत्कृष्टता का अर्थ केवल पेशेवर सफलता नहीं है. उत्कृष्टता का संबंध व्यक्ति के चरित्र, मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व से भी है. यदि शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील, नैतिक और मानवीय नहीं बनाती तो उसकी उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं. आज विश्व जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता, मानसिक स्वास्थ्य संकट और सांस्कृतिक विखंडन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है. इन समस्याओं का समाधान केवल विज्ञान और तकनीक से नहीं होगा. इसके लिए ऐसे शिक्षित नागरिकों की आवश्यकता है जो करुणा, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को समझते हों.

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. ऐसे सपनों को साकार करने की शक्ति शिक्षा ही प्रदान करती है. जिज्ञासा उन सपनों को जन्म देती है और शिक्षा उन्हें वास्तविकता में बदलने का मार्ग दिखाती है. यही कारण है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर निर्भर करता है.

इक्कीसवीं सदी में राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा केवल संसाधनों की नहीं, बल्कि ज्ञान और नवाचार की होगी. जो देश अपने बच्चों और युवाओं की जिज्ञासा को पहचानेंगे, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और उनकी प्रतिभा को विकसित करेंगे, वही विश्व का नेतृत्व करेंगे. भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है. यह जनसांख्यिकीय शक्ति तभी राष्ट्रीय संपदा में बदल सकती है जब उसे शिक्षा, कौशल और नवाचार से जोड़ा जाए.

अंततः, कहा जा सकता है कि जिज्ञासा से उत्कृष्टता तक की यात्रा ही शिक्षा की वास्तविक यात्रा है. जिज्ञासा ज्ञान को जन्म देती है, ज्ञान विवेक को विकसित करता है और विवेक उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त करता है. शिक्षा केवल व्यक्ति का भाग्य नहीं बदलती, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य को भी आकार देती है. विकसित भारत का स्वप्न तभी साकार होगा, जब प्रत्येक बच्चे के प्रश्न को महत्व मिलेगा, प्रत्येक शिक्षक को सम्मान मिलेगा और शिक्षा को जीवन परिवर्तन के सबसे शक्तिशाली साधन के रूप में स्वीकार किया जाएगा.

ज्ञान का प्रत्येक दीपक किसी-न-किसी जिज्ञासा की लौ से प्रज्वलित हुआ है. इसलिए, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों और युवाओं के मन में उठनेवाले प्रश्नों को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें नई उड़ान दें. भविष्य की हर खोज, हर उपलब्धि और हर उत्कृष्टता की शुरुआत एक छोटे-से प्रश्न से ही होती है. ■

ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता जाल

बच्चों और युवाओं का बदलता संसार

> "ऑनलाइन गेमिंग के युवाओं और बच्चों पर दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं. यह एकाग्रता और समस्या सुलझाने की क्षमता को सुधारता है, जबकि अत्यधिक उपयोग से मानसिक तनाव, शारीरिक निष्क्रियता, नींद की कमी और सामाजिक अलगाव का खतरा बढ़ जाता है."

सुबह का समय है. विद्यालय जाने की तैयारी चल रही है. घर के एक कोने में बैठा किशोर अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पूरी तरह केंद्रित है. मां कई बार नाश्ते के लिए आवाज देती है, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन से नहीं हटता. दूसरी ओर, एक कॉलेज छात्र रात-भर ऑनलाइन गेम खेलने के कारण सुबह की कक्षा में सोता हुआ दिखाई देता है. ऐसे दृश्य आज किसी एक घर या शहर तक सीमित नहीं हैं. यह बदलते भारत की एक नई सामाजिक वास्तविकता है, जहां ऑनलाइन गेमिंग मनोरंजन का साधन-भर नहीं रह गई है, बल्कि लाखों बच्चों और युवाओं की जीवनशैली को प्रभावित करनेवाली शक्ति बन चुकी है.

डॉ. मो. रहमतुल्लाह

डिजिटल क्रांति के इस युग में इंटरनेट और स्मार्टफोन ने जीवन को आसान बनाया है. सूचना तक पहुंच पहले से कहीं अधिक सरल हुई है. शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और संचार के क्षेत्र में तकनीक ने नए अवसर पैदा किए हैं. किंतु, तकनीक के इसी विस्तार ने कुछ नई चुनौतियां भी जन्म दी हैं. ऑनलाइन गेमिंग उनमें सबसे प्रमुख है. विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में इसकी बढ़ती लोकप्रियता अब एक गंभीर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक चिंता का विषय बनती जा रही है.

कोविड-19 महामारी के दौरान जब विद्यालय बंद थे और लोग अपने घरों तक सीमित थे, तब ऑनलाइन गेमिंग ने मनोरंजन और समय बिताने के साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अनेक परिवारों में बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के लिए मोबाइल का उपयोग करते थे और उसी उपकरण पर गेम भी खेलते थे. महामारी समाप्त होने के बाद भी यह आदत कम नहीं हुई, बल्कि कई मामलों में यह स्थायी व्यवहार बन गई. आज स्थिति यह है कि लाखों बच्चे और युवा प्रतिदिन कई घंटे मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम खेलने में व्यतीत कर रहे हैं.

ऑनलाइन गेमिंग का आकर्षण केवल खेल तक सीमित नहीं है. इसमें प्रतिस्पर्धा, रोमांच, उपलब्धि और सामाजिक पहचान का मिश्रण होता है. खेल में नए स्तर हासिल करना, उच्च स्कोर बनाना, पुरस्कार जीतना और दूसरे खिलाड़ियों को हराना युवाओं को लगातार खेलते रहने के लिए प्रेरित करता है. यही कारण है कि अनेक गेम इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि खिलाड़ी बार-बार लौटकर आए. धीरे-धीरे यह मनोरंजन की सीमा पारकर निर्भरता और फिर लत का रूप ले लेता है. मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऑनलाइन गेमिंग मस्तिष्क में डोपामिन नामक रसायन के स्राव को बढ़ाती है. यह वही रसायन है जो किसी उपलब्धि या आनंद की अनुभूति के समय सक्रिय होता है. प्रत्येक जीत या पुरस्कार खिलाड़ी को क्षणिक संतुष्टि प्रदान करता है. यही संतुष्टि बार-बार गेम खेलने की इच्छा को जन्म देती है. जब खिलाड़ी खेल नहीं पाता तो उसे बेचैनी, चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस होने लगता है. यही स्थिति धीरे-धीरे व्यसन का रूप धारण कर लेती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि गेमिंग की लत केवल समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है. अत्यधिक गेम खेलनेवाले बच्चों और युवाओं में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होने लगती है. स्मरण शक्ति प्रभावित होती है. पढ़ाई में रुचि घटती है और कई बार अवसाद तथा चिंता जैसी समस्याएं भी

उत्पन्न हो जाती हैं. कुछ मामलों में सामाजिक अलगाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति वास्तविक जीवन के संबंधों की अपेक्षा आभासी दुनिया को अधिक महत्व देने लगता है.

इस समस्या का प्रभाव शिक्षा पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक अक्सर यह शिकायत करते हैं कि विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई की अपेक्षा मोबाइल स्क्रीन पर अधिक रहता है. गृहकार्य अधूरा रह जाता है. कक्षा में एकाग्रता कम हो जाती है. परीक्षा परिणाम प्रभावित होते हैं. कई छात्र देर रात तक गेम खेलने के कारण पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, जिसका सीधा असर उनकी सीखने की क्षमता पर पड़ता है.

ऑनलाइन गेमिंग का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष भी है. पारंपरिक खेल बच्चों और युवाओं को मैदान, मित्रता, सहयोग और शारीरिक गतिविधि से जोड़ते थे. आज उनकी जगह आभासी खेलों ने लेना शुरू कर दिया है. परिणामस्वरूप, बच्चों का सामाजिक संपर्क सीमित हो रहा है. परिवार के सदस्यों के साथ संवाद कम हो रहा है. कई घरों में एक ही कमरे में बैठे लोग भी अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त दिखाई देते हैं. यह स्थिति केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना में हो रहे बदलाव का संकेत है.

शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव भी कम गंभीर नहीं हैं. घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठे रहने से आंखों में दर्द, सिरदर्द, गर्दन और कमर की समस्याएं बढ़ रही हैं. शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण मोटापा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है. चिकित्सकों के अनुसार, किशोरावस्था में सक्रिय जीवनशैली का अभाव भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है.

आर्थिक दृष्टि से भी ऑनलाइन गेमिंग एक उभरती हुई चुनौती है. अधिकांश गेम प्रारंभ में निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन उनमें आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रीमियम सुविधाओं की खरीद आवश्यक होती है. बेहतर हथियार, विशेष शक्तियां, नए पात्र और अतिरिक्त अवसर पाने के लिए खिलाड़ियों को भुगतान करना पड़ता है. कई बच्चे और किशोर अभिभावकों की जानकारी के बिना ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं. कुछ मामलों में बड़ी आर्थिक हानि की घटनाएं भी सामने आई हैं. इससे परिवारों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है.

भारत आज विश्व के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक है. देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. स्मार्टफोन अब गांवों तक पहुंच चुके हैं. यह परिवर्तन विकास का संकेत है, लेकिन इसके साथ डिजिटल जिम्मेदारी का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है. यदि तकनीक का उपयोग संतुलित और जिम्मेदार तरीके से नहीं किया गया तो इसके दुष्परिणाम समाज को लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं. दक्षिण कोरिया, जापान और चीन जैसे देशों ने गेमिंग की लत को सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौती के रूप में स्वीकार किया है. वहां बच्चों के लिए गेम खेलने के समय पर सीमाएं निर्धारित की गई हैं तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. भारत में भी इस दिशा में गंभीर विमर्श की आवश्यकता है. केवल प्रतिबंध समाधान नहीं हो सकता. आवश्यकता संतुलित नियमन और व्यापक जागरूकता की है.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या के समाधान में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. माता-पिता को बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए. केवल मोबाइल छीन लेना समाधान नहीं है. बच्चों की भावनाओं, रुचियों और समस्याओं को समझना आवश्यक है. यदि परिवार में सकारात्मक वातावरण होगा तो बच्चे आभासी दुनिया की अपेक्षा वास्तविक जीवन में अधिक रुचि लेंगे. अभिभावकों को स्वयं भी डिजिटल उपकरणों के संतुलित उपयोग का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए.

विद्यालयों और महाविद्यालयों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी. डिजिटल साक्षरता को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए. विद्यार्थियों को यह समझाया जाना चाहिए कि तकनीक का उपयोग ज्ञान और विकास के लिए है, न कि उसपर निर्भर हो जाने के लिए. खेलकूद, साहित्य, संगीत, कला और सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है.

सरकार और नीति-निर्माताओं के लिए भी यह समय गंभीर चिंतन का है. आयु आधारित गेम वर्गीकरण, सुरक्षित भुगतान व्यवस्था, अभिभावकीय नियंत्रण प्रणाली और डिजिटल स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देश विकसित किए जाने चाहिए. साथ ही, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और परामर्श केंद्रों को मजबूत बनाना आवश्यक है, ताकि गेमिंग की लत से प्रभावित बच्चों और युवाओं को समय पर सहायता मिल सके.

निःसंदेह, ऑनलाइन गेमिंग आधुनिक तकनीकी युग की एक वास्तविकता है. इसके सकारात्मक पहलुओं को नकारा नहीं जा सकता. यह मनोरंजन, सीखने और कौशल विकास का माध्यम भी बन सकता है. लेकिन, जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तब व्यक्ति, परिवार और समाज, तीनों के लिए चुनौती बन जाता है. इसलिए, आवश्यक है कि हम इसे केवल मनोरंजन का विषय न मानें, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न के रूप में देखें.

आज जरूरत तकनीक से दूरी बनाने की नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलित संबंध स्थापित करने की है. यदि परिवार, विद्यालय, समाज और सरकार मिलकर जिम्मेदार डिजिटल संस्कृति का निर्माण करें तो ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है. इस पूंजी को आभासी लत के जाल से बचाकर रचनात्मक और उत्पादक दिशा में ले जाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. यही भविष्य के स्वस्थ, जागरूक और सशक्त भारत की आधारशिला बनेगा. ■

कृषि

गंभीर चुनौती

मॉनसून की अनिश्चितता और भारत का कृषि अर्थतंत्र

डॉ. शगुफ्ता निगार

भारत की पहचान एक कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में रही है. यहां की सभ्यता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का विकास कृषि के इर्द-गिर्द हुआ है. आज भी करोड़ों लोगों की आजीविका खेती और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है. भारतीय किसान सदियों से प्रकृति के साथ संवाद करते हुए खेती करता आया है. इस संवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार मॉनसून रहा है. यही कारण है कि भारतीय मॉनसून को केवल एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि देश की आर्थिक धड़कन माना जाता है.

हर वर्ष जून के आगमन के साथ किसानों की निगाहें आसमान की ओर उठ जाती हैं. खेत तैयार रहते हैं, बीज तैयार रहते हैं और उम्मीदें भी तैयार रहती हैं. किंतु, पिछले कुछ वर्षों में मॉनसून का स्वभाव तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है. कभी समय से पहले वर्षा हो जाती है, कभी देर से. कहीं बादल बरसते नहीं और कहीं इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि खेत जलमग्न हो जाते हैं. यह अनिश्चितता केवल मौसम की समस्या नहीं है, बल्कि भारत के कृषि अर्थतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है.

जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है. पृथ्वी का बढ़ता तापमान, पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन मौसम के पारंपरिक चक्र को प्रभावित कर रहे हैं. परिणामस्वरूप, वर्षा के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में वर्षा का वितरण अधिक असंतुलित हुआ है. कम दिनों में अत्यधिक वर्षा और लंबे समय तक शुष्क अवधि अब सामान्य घटनाएं बनती जा रही हैं.

भारतीय कृषि की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज भी देश की लगभग आधी कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है. बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में खेती का भाग्य मॉनसून की कृपा पर टिका रहता है. ऐसे में यदि वर्षा सामान्य से कम हो जाए या समय पर न पहुंचे तो किसानों के सामने संकट खड़ा हो जाता है. धान, मक्का, दलहन, तिलहन और अन्य खरीफ फसलें सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं. उत्पादन में गिरावट का अर्थ है किसानों की आय में कमी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ठहराव.

मॉनसून की अनिश्चितता का प्रभाव खेतों तक सीमित नहीं रहता. इसका असर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देता है. कृषि क्षेत्र देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है. जब फसल उत्पादन घटता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति कम हो जाती है. किसान कृषि यंत्र, वाहन, निर्माण

> “अनिश्चित मॉनसून और कृषि अर्थव्यवस्था का सीधा और गहरा संबंध है, क्योंकि भारत की लगभग आधी खेती आज भी वर्षा पर निर्भर है. मॉनसून में देरी या असमान बारिश से खरीफ फसलों जैसे धान, दलहन और तिलहन आदि की बुवाई और पैदावार प्रभावित होती है, जिससे ग्रामीण आय घटती है और अंततः खाद्य मुद्रास्फीति व आर्थिक मंदी का खतरा पैदा होता है.

सामग्री और उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद कम कर देते हैं. परिणामस्वरूप, अनेक उद्योगों की मांग प्रभावित होती है. यही कारण है कि अर्थशास्त्री मॉनसून को भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक मानते हैं.

खाद्य मुद्रास्फीति भी मॉनसून की अनिश्चितता से जुड़ी एक बड़ी समस्या है. यदि धान, दालें, सब्जियां और तिलहन का उत्पादन कम होता है तो बाजार में उनकी उपलब्धता घट जाती है. मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं. इसका सीधा प्रभाव आम नागरिकों की रसोई पर पड़ता है. गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बढ़ती खाद्य कीमतें अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाती हैं. इस प्रकार, मॉनसून की विफलता किसान और उपभोक्ता, दोनों को प्रभावित करती है.

बिहार जैसे राज्यों में यह चुनौती और अधिक गंभीर है. उत्तर बिहार के कई जिले हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है. एक ओर किसानों की फसलें जलमग्न हो जाती हैं तो दूसरी ओर कई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता. यह विरोधाभासी स्थिति राज्य की कृषि व्यवस्था के समक्ष जटिल प्रश्न खड़े करती है.

सिंचाई सुविधाओं का अभाव भी समस्या को बढ़ाता है. यद्यपि देश में नहरों, ट्यूबवेलों और अन्य सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी बड़ी मात्रा में कृषि भूमि अभी भी वर्षा आधारित है. जलवायु परिवर्तन के इस दौर में केवल मॉनसून पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण होता जा रहा है. जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है.

आज कृषि पर वैश्विक परिस्थितियों का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है. उर्वरकों की कीमतें, ऊर्जा लागत और कृषि उपकरणों का बाजार अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित होता है. रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे घटनाक्रमों ने यह दिखा दिया कि वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान आने पर कृषि लागत कितनी तेजी से बढ़ सकती है. जब किसान पहले से ही मौसम की अनिश्चितता से जूझ रहा हो, तब बढ़ती लागत उसकी कठिनाइयों को और बढ़ा देती है.

ऐसी परिस्थितियों में समाधान केवल पारंपरिक खेती में नहीं, बल्कि नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में निहित है. जलवायु-अनुकूल कृषि आज समय की आवश्यकता बन चुकी है. ऐसी कृषि व्यवस्था विकसित करनी होगी जो बदलते मौसम के प्रभावों को सहन कर सके. सूखा-सहनशील और अल्पावधि फसल किस्मों का उपयोग, फसल विविधीकरण, जैविक संसाधनों का संरक्षण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का प्रयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.

फसल विविधीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. यदि किसान केवल एक फसल पर निर्भर रहेगा तो जोखिम अधिक होगा. दलहन, तिलहन, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन को कृषि के साथ जोड़कर आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित किए जा सकते हैं. इससे प्राकृतिक आपदाओं के समय आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता है.

डिजिटल तकनीक भी कृषि के भविष्य को नई दिशा दे रही है. मौसम पूर्वानुमान, उपग्रह आधारित निगरानी, मोबाइल कृषि परामर्श और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान किसानों को अधिक सटीक निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर रहे हैं. यदि इन तकनीकों को गांवों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए तो मॉनसून से जुड़े जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि और प्राकृतिक खेती से संबंधित कार्यक्रम किसानों को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं. किंतु, योजनाओं की वास्तविक सफलता तभी संभव है, जब उनका लाभ अंतिम किसान तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे.

वास्तव में मॉनसून की अनिश्चितता हमें यह संदेश देती है कि कृषि विकास की पारंपरिक सोच में परिवर्तन आवश्यक है. अब केवल अधिक उत्पादन ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि टिकाऊ और जलवायु-सुरक्षित कृषि व्यवस्था का निर्माण भी उतना ही आवश्यक है. जल, भूमि और जैव विविधता के संरक्षण के साथ कृषि को भविष्य के लिए तैयार करना होगा.

अंततः, कहा जा सकता है कि भारत की कृषि आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है. एक ओर जलवायु परिवर्तन की चुनौती है तो दूसरी ओर विज्ञान और तकनीक के नए अवसर उपलब्ध हैं. यदि सरकार, वैज्ञानिक समुदाय, कृषि संस्थान और किसान मिलकर दूरदर्शी रणनीति अपनाएं तो मॉनसून की अनिश्चितता को विकास के अवसर में बदला जा सकता है. भारत की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक स्थिरता इसी पर निर्भर करती है.

मॉनसून की बूंदें केवल खेतों को ही नहीं सींचतीं, वे देश की अर्थव्यवस्था, समाज और भविष्य को भी जीवन प्रदान करती हैं. इसलिए, मॉनसून की अनिश्चितता को समझना और उससे प्रभावी ढंग से निबटना आज के भारत की सबसे बड़ी कृषि एवं आर्थिक प्राथमिकताओं में से एक है. ■

एक बुलबुल के घोंसले से जीवन का सबक !

प्रो. मुश्ताक अहमद

प्रकृति की पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ अपने भीतर एक नई कथा और एक नया संदेश समेटे हुए है. यदि मनुष्य कुछ क्षण ठहरकर अपने आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अवलोकन करे तो उसे अनुभव होगा कि जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला किसी विश्वविद्यालय या पुस्तकालय में नहीं, बल्कि प्रकृति की निस्तब्ध गोद में बसती है. पक्षियों का मधुर कलरव, वृक्षों की मूक सरसराहट, पुष्पों की सुगंध और बहते जल की कलकल- ये सभी मनुष्य को ऐसे जीवन-पाठ पढ़ाते हैं, जिन्हें अनेक ग्रंथ भी पूरी तरह नहीं सिखा पाते.

कुछ दिन पहले मेरे घर के आंगन में रखे एक कैक्टस के गमले ने अनायास ही मेरा ध्यान आकर्षित किया. एक नन्ही-सी बुलबुल ने न जाने क्यों उसी कांटों से भरे पौधे को अपने आशियाने के लिए चुना. उसने अथक परिश्रम, धैर्य और अपार ममता के साथ कांटों के बीच अपना छोटा-सा घोंसला बनाया. यह दृश्य मानो यह संदेश दे रहा था कि जीवन सदैव सरल मार्गों का नाम नहीं है, कभी-कभी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए कांटों का सहारा भी लेना पड़ता है.

कुछ दिनों बाद उस घोंसले में तीन छोटे-छोटे अंडे दिखाई दिए. फिर वह शुभ क्षण भी आया, जब उन अंडों से जीवन ने आंखें खोलीं. नन्हे बच्चे अपनी छोटी-सी चोंच खोलकर मां की प्रतीक्षा करते रहते और मां प्रातः से संध्या तक उनके लिए भोजन जुटाने में लगी रहती. वह बार-बार उड़ती, दाना लाती, बच्चों को खिलाती और फिर अगली उड़ान के लिए निकल पड़ती. उसके लिए न प्रखर धूप कोई बाधा थी, न वर्षा की बूंदें और न ही थकान का कोई अर्थ था. उसकी पूरी दुनिया उसके वे तीन नन्हे बच्चे ही थे.

मैं प्रतिदिन मौन भाव से इस पूरे दृश्य का अवलोकन करता. धीरे-धीरे मुझे अनुभव हुआ कि मैं केवल एक पक्षी को नहीं देख रहा हूं, बल्कि प्रकृति के एक शाश्वत सत्य को अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहा हूं. वह सत्य था- मातृत्व का प्रेम, जिसकी न कोई सीमा होती है, न कोई भाषा और न कोई धर्म.

एक बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया. जब भी कोई अपरिचित व्यक्ति मेरे घर आता या आंगन में हल्की-सी आहट होती, बुलबुल बेचैन हो उठती. वह लगातार चहचहाती, एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकती और बार-बार अपने घोंसले के चारों ओर मंडराने लगती. मानो वह हर आनेवाले से विनम्र निवेदन कर रही हो- 'ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें कोई क्षति न पहुंचाए.'

आज का भौतिकवादी युग मनुष्य को मशीन बनाता जा रहा है. रिश्तों की ऊष्मा कम होती जा रही है, माता-पिता और संतानों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं तथा व्यस्तता ने प्रेम के सहज प्रदर्शन को सीमित कर दिया है. ऐसे समय में एक नन्ही-सी बुलबुल हमें यह सिखाती है कि जीवन की वास्तविक सुंदरता प्रेम, त्याग, उत्तरदायित्व और संरक्षण में निहित है.

उस दृश्य को देखकर मेरे मन में एक अद्भुत भाव जाग उठता. मुझे अपनी मां का स्मरण हो आता, उन सभी माताओं का स्मरण हो आता जो अपना संपूर्ण जीवन अपनी संतान की खुशियों पर न्योछावर कर देती हैं. वास्तव में मां का हृदय इस सृष्टि का सबसे निस्वार्थ हृदय होता है.

वह अपने हिस्से की सारी खुशियां भी अपनी संतान पर अर्पित कर देती है और बदले में किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रखती.

बुलबुल की इस व्याकुलता ने मुझे यह सोचने पर भी विवश किया कि पशु-पक्षियों के भीतर भी संवेदनाओं का वही संसार बसता है, जिसे हम प्रायः अनदेखा कर देते हैं. वे भी प्रेम करते हैं, भय का अनुभव करते हैं, बिछड़ने का दुःख सहते हैं और अपनी संतानों की रक्षा के लिए हर संकट उठाने को तत्पर रहते हैं. विडंबना यह है कि स्वयं को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहनेवाला मनुष्य ही इन मानवीय भावनाओं से दूर होता जा रहा है.

आज का भौतिकवादी युग मनुष्य को मशीन बनाता जा रहा है. रिश्तों की ऊष्मा कम होती जा रही है, माता-पिता और संतानों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं तथा व्यस्तता ने प्रेम के सहज प्रदर्शन को सीमित कर दिया है. ऐसे समय में एक नन्ही-सी बुलबुल हमें यह सिखाती है कि जीवन की वास्तविक सुंदरता प्रेम, त्याग, उत्तरदायित्व और संरक्षण में निहित है.

इस घटना ने मुझे यह भी अनुभव कराया कि प्रकृति का प्रत्येक दृश्य ईश्वर की अनंत सत्ता का साक्षी है. पवित्र कुरान बार-बार मनुष्य को सृष्टि पर चिंतन करने का आह्वान करता है, ताकि वह अपने सृष्टिकर्ता की महिमा को पहचान सके. एक छोटा-सा पक्षी भी हमें धैर्य, परिश्रम, कर्तव्यबोध, त्याग और प्रेम का पाठ पढ़ा सकता है, यदि हमारे भीतर देखने की दृष्टि और अनुभव करने की संवेदना जीवित हो.

इन दिनों मैंने बुलबुल और उसके बच्चों को किसी प्रकार का व्यवधान न पहुंचाने का पूरा प्रयास किया. मैं केवल दूर से उनके जीवन के इन सुंदर क्षणों को निहारता रहा. मुझे ऐसा प्रतीत होता था मानो मेरे आंगन में केवल एक घोंसला नहीं, बल्कि प्रेम की एक छोटी-सी पाठशाला स्थापित हो गई हो, जहां प्रतिदिन मौन रहकर मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा हो.

कुछ ही दिनों में वे नन्हे बच्चे बड़े होने लगे. उनके पंखों में शक्ति आई. उन्होंने घोंसले के किनारे खड़े होकर पहली बार इस विस्तृत संसार को देखा. फिर एक दिन ऐसा आया, जब उन्होंने अपने जीवन की पहली उड़ान भरी. मां उनके साथ-साथ उड़ रही थी, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य की पहली सफलता पर प्रसन्न होता है और जैसे कोई मां अपने बच्चे के पहले कदम पर मुस्कुरा उठती है.

उस दृश्य ने मेरी आंखों को नम कर दिया. घोंसला वहीं रह गया, किंतु उसके निवासी असीम आकाश की ऊंचाइयों में विलीन हो गए. मुझे लगा कि जीवन का यही सनातन नियम है. माता-पिता अपनी संतानों का पालन-पोषण करते हैं, उन्हें स्नेह से संवारते हैं, उन्हें उड़ना सिखाते हैं और फिर एक दिन उन्हें उनकी अपनी मंजिलों की ओर विदा कर देते हैं.

वह नन्ही-सी बुलबुल मेरे लिए केवल एक पक्षी नहीं रही, बल्कि एक गुरु बन गई. उसने मुझे सिखाया कि प्रेम का वास्तविक अर्थ सुरक्षा, त्याग, निस्वार्थ सेवा और दूसरों के लिए जीने में निहित है. शायद यही वह संदेश है, जिसकी आज के मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता है.

यदि हम प्रकृति के इन मौन संदेशों को समझना सीख लें तो हमारे समाज में प्रेम बढ़ेगा, परिवार अधिक सुदृढ़ होंगे, बड़ों के प्रति सम्मान पुनः स्थापित होगा और नई पीढ़ी का चरित्र अधिक संवेदनशील बनेगा. एक बुलबुल का घोंसला देखने में भले ही बहुत छोटा हो, पर उसके भीतर संपूर्ण सृष्टि का एक महान सत्य छिपा है- मां का वात्सल्य जो प्रत्येक प्राणी में समान रूप से विद्यमान, शाश्वत, अमर और अनुपम है. ■

AI जनरेटेड म्यूजिक फ्यूचर या थ्रेट

दिव्यांजलि वर्मा

"जब मशीनें गाने बनाने लगें तो क्या होगा कलाकारों का भविष्य"

कल्पना कीजिए... आप अपने पसंदीदा ऐप पर एक नया गाना सुनते हैं. उसकी धुन दिल को छू जाती है, आवाज बिल्कुल किसी प्रोफेशनल सिंगर जैसी लगती है और बोल भी शानदार होते हैं. लेकिन, बाद में आपको पता चलता है कि वह गाना किसी इंसान ने नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने बनाया है. क्या तब भी वह गाना आपको उतना ही पसंद आएगा?

कुछ साल पहले तक यह केवल फिल्मों या साइंस फिक्शन की दुनिया का हिस्सा लगता था. लेकिन, आज एआई न सिर्फ तस्वीरें बना रहा है, बल्कि गाने लिख रहा है, धुन तैयार कर रहा है और इंसानों जैसी आवाज में गा भी रहा है. यही वजह है कि एआई जनरेटेड म्यूजिक आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोग इसे संगीत का भविष्य मानते हैं, जबकि कुछ इसे कलाकारों की पहचान और रचनात्मकता के लिए खतरा मानते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एआई संगीत की दुनिया में नई क्रांति लाएगा या इंसानी कला को पीछे छोड़ देगा?

क्या है एआई जनरेटेड म्यूजिक

एआई जनरेटेड म्यूजिक का मतलब है ऐसा संगीत, जिसे एआई की मदद से तैयार किया जाए. एआई लाखों पुराने गानों, धुनों और संगीत शैलियों का अध्ययन कर सकता है और फिर कुछ ही मिनटों में नया गाना बना सकता है. कई एआई टूल्स केवल एक छोटा-सा निर्देश मिलने पर बोल, धुन, बैकग्राउंड म्यूजिक और यहां तक कि गायकी भी तैयार कर देते हैं.

क्यों बढ़ रही इसकी लोकप्रियता

एआई की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार है. जहां एक गाना बनाने में कई दिनों या हफ्तों का समय लग सकता है, वहीं एआई कुछ ही मिनटों में अलग-अलग स्टाइल के कई गाने तैयार कर देता है. आज यूट्यूबर, फिल्म निर्माता, विज्ञापन कंपनियां और सोशल मीडिया क्रिएटर तेजी से एआई म्यूजिक का उपयोग कर रहे हैं. इससे समय और खर्च, दोनों की बचत होती है. छोटे कलाकारों के लिए भी यह एक अच्छा अवसर है, क्योंकि अब वे कम संसाधनों में भी अपने संगीत के विचारों को वास्तविक रूप दे सकते हैं.

क्या एआई ले सकता है कलाकारों की जगह

यही सबसे बड़ा सवाल है. संगीत केवल सुरों और शब्दों का मेल नहीं होता, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति भी होता है. जब कोई कलाकार प्रेम, दर्द, संघर्ष या खुशी से जुड़ा गीत लिखता है तो उसमें उसके अपने अनुभव झलकते हैं. यही कारण है कि कुछ गाने वर्षों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं. एआई पैटर्न समझ सकता है, लेकिन वह इंसानों की तरह महसूस नहीं कर सकता. वह धुन बना सकता है लेकिन किसी याद, रिश्ते या दर्द को जी नहीं सकता. शायद यही अंतर इंसानी संगीत को हमेशा खास बनाए रखेगा.

कॉपीराइट और नैतिक चुनौतियां

एआई म्यूजिक के साथ कई सवाल भी जुड़े हैं. अगर, एआई किसी मशहूर गायक जैसी आवाज बनाकर नया गाना तैयार करे तो उसका मालिक कौन होगा? अगर, किसी कलाकार की शैली की नकल की जाए तो क्या यह सही होगा? आज दुनिया-भर में इस विषय पर कानूनी और नैतिक बहस चल रही है. कलाकार चाहते हैं कि उनकी रचनाओं और आवाज का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बगैर न किया जाए. इसलिए, आनेवाले समय में एआई म्यूजिक के लिए स्पष्ट नियम और कानून बनाना बेहद जरूरी होगा.

कैसा हो सकता है भविष्य

कई विशेषज्ञों का मानना है कि एआई कलाकारों की जगह लेने के बजाय उनका सहयोगी बन सकता है. जैसे कैलकुलेटर आने से गणित खत्म नहीं हुआ और कैमरा आने से पेंटिंग की कला समाप्त नहीं हुई, उसी तरह एआई के आने से संगीत भी खत्म नहीं होगा. भविष्य में संगीतकार एआई की मदद से नए आइडिया खोजेंगे, शुरुआती धुन तैयार करेंगे, फिर उसमें अपनी रचनात्मकता और भावनाएं जोड़कर पहले से बेहतर संगीत तैयार करेंगे. तकनीक और इंसानी प्रतिभा का मेल संगीत को नई ऊंचाई दे सकता है. एआई जनरेटेड म्यूजिक न तो पूरी तरह भविष्य है और न ही पूरी तरह खतरा. यह एक नई तकनीक है, जिसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं. अगर, एआई को कलाकारों की जगह लेने के बजाय उनकी मदद करनेवाले साथी के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो यह संगीत की दुनिया को नए आयाम तक ले जा सकता है लेकिन अगर रचनात्मकता, मौलिकता और कलाकारों के अधिकारों की अनदेखी की गई तो यही तकनीक कई चुनौतियां भी पैदा कर सकती है.

आखिर में, मशीनें धुन बना सकती हैं, लेकिन किसी गीत में जान, एहसास और यादें सिर्फ इंसान ही भर सकता है. शायद भविष्य का खूबसूरत संगीत वही होगा, जहां तकनीक और इंसानी दिल एकसाथ सुर मिलाएंगे. ■

सूर्य और सात घोड़ों का रहस्य

सुनील कुमार मिश्रा

हिंदू धर्म में देवी-देवताओं तथा उनसे जुड़ी कहानियों का इतिहास काफी बड़ा है. विभिन्न देवी-देवताओं का चित्रण, उनकी वेशभूषा और यहां तक कि वे किस सवारी पर सवार होते थे, ये तथ्य भी काफी रोचक हैं. विघ्नहर्ता गणेश जी एक मूषक यानी कि चूहे पर सवार होते हैं, जिसे देख हर कोई अचंभित होता है. गणेश जी के बाद यदि किसी देवी या देवता की सवारी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वे हैं सूर्य भगवान. सूर्य भगवान जिन्हें आदित्य, भानु और रवि भी कहा जाता है, सात घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ पर सवार होते हैं. इन घोड़ों की लगाम अरुण देव के हाथ होती है. लेकिन, सूर्य देव द्वारा सात ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है ?

सूर्य भगवान के रथ के सात घोड़ों के संदर्भ में पुराणों में उल्लेख है और कई कहानियां प्रचलित हैं. विशाल रथ और साथ में उसे चलानेवाले सात घोड़े तथा सारथी अरुण देव, यह किसी भी सूर्य मंदिर में विराजमान सूर्य देव की मूर्ति का वर्णन है. भारत में प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य तथा उनके रथ को काफी अच्छे से दर्शाता है. सूर्य भगवान के रथ को संभालनेवाले सात घोड़ों के नाम हैं- गायत्री, भ्राति, उष्णिक, जगति, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति. ये सात घोड़े एक सप्ताह के सात दिनों को दर्शाते हैं. ये सात घोड़े इंद्रधनुष को भी दर्शाते हैं. सूर्य के प्रकाश में सात विभिन्न रंगों की रोशनी पाई जाती है जो इंद्रधनुष का निर्माण करती है. सूर्य भगवान के सात घोड़ों को भी इंद्रधनुष के इन्हीं सात रंगों से जोड़ा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम इन घोड़ों को ध्यान से देखें तो प्रत्येक घोड़े का रंग भिन्न है. एक और कारण है जो यह बताता है कि सूर्य भगवान के रथ को चलानेवाले सात घोड़े स्वयं सूरज की रोशनी का ही प्रतीक हैं. सूर्य भगवान की रथ के साथ बनाई गई तस्वीर या मूर्ति में सात अलग-अलग घोड़े होते हैं, ठीक वैसा ही जैसा पौराणिक कहानियों में बताया जाता है, लेकिन कई बार तस्वीरें और मूर्तियां इससे थोड़ी अलग भी बनाई जाती हैं. रथ के साथ केवल एक घोड़े पर सात सिर को दर्शाया जाता है. इसका मतलब है कि केवल एक शरीर से ही सात अलग-अलग घोड़ों की उत्पत्ति होती है. ठीक उसी प्रकार से जैसे सूरज की रोशनी से सात अलग रंगों की रोशनी निकलती है.

> सूर्य भगवान के रथ को संभालनेवाले सात घोड़ों के नाम हैं- गायत्री, भ्राति, उष्णिक, जगति, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति. ये सात घोड़े एक सप्ताह के सात दिनों को दर्शाते हैं.

सूर्य भगवान से जुड़ी एक और खास बात यह है कि उनके 11 भाई हैं, जिन्हें एकत्रित रूप में आदित्य भी कहा जाता है. यही कारण है कि सूर्य देव को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है. सूर्य भगवान के अलावा 11 भाई- अंश, आर्यमान, भाग, दक्ष, धात्री, मित्र, पुशण, सवित्र, सूर्या, वरुण एवं वमन हैं. सभी कश्यप तथा अदिति की संतान हैं. पौराणिक इतिहास के अनुसार, कश्यप तथा अदिति की आठ या नौ संतानें बताई जाती हैं, लेकिन बाद में यह संख्या 12 बताई गई. सूर्य देव तथा उनके भाई मिलकर वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं. सूर्य देव की दो पत्नियां- संज्ञा एवं छाया हैं, जिनसे उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी. इन संतानों में भगवान शनि और यमराज को मनुष्य जाति का न्यायाधिकारी माना जाता है. जहां मानव जीवन का सुख तथा दुःख भगवान शनि पर निर्भर करता है, वहीं शनि के छोटे भाई यमराज द्वारा आत्मा की मुक्ति की जाती है. इसके अलावा यमुना, तपती, अश्विनी तथा वैवस्वत मनु भी भगवान सूर्य की संतानें हैं. आगे चलकर मनु ही मानव जाति के प्रथम पूर्वज बने.

पौराणिक तथ्यों के अनुसार, सूर्य भगवान जिस रथ पर सवार हैं, उसके नीचे केवल एक पहिया लगा है, जिसमें 12 तीलियां लगी हैं. यह अकेला पहिया एक वर्ष को दर्शाता है और उसकी 12 तीलियां 12 महीनों का वर्णन करती हैं. एक पौराणिक उल्लेख के अनुसार, सूर्य भगवान के रथ के समस्त 60 हजार बालखिल्य ऋषि, जिनका आकार केवल मनुष्य के हाथ के अंगूठे जितना ही है, वे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं. इसके साथ ही गांधर्व एवं पन्नग उनके सामने गाते हैं और अप्सराएं उन्हें खुश करने के लिए नृत्य प्रस्तुत करती हैं. कहा जाता है कि इन्हीं प्रतिक्रियाओं पर संसार में ऋतुओं का विभाजन किया जाता है. इस प्रकार, केवल पौराणिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों से भी जुड़ा है भगवान सूर्य का यह विशाल रथ. ■

वक्त रहते पहचानें डायबिटीज की संभावना

डॉ. आरके प्रसाद

डायबिटीज की समय पर पहचान के लिए बार-बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना और बगैर वजह वजन कम होना जैसे लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है. खून में शुगर का स्तर बढ़ने पर शरीर कई तरह के चेतावनी संकेत देता है, जिन्हें पहचानकर सतर्क होना आवश्यक है.

भारत में डायबिटीज (मधुमेह) की बीमारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है. दुनिया में हमारा देश मधुमेह की राजधानी बन गया है. आज देश में दस करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और इससे कहीं ज्यादा इसके रास्ते पर हैं. डायबिटीज पूरे शरीर को दीमक की तरह खा जाता है. मैं सतर्क कर रहा हूं कि आपलोगों ने इसे आज नहीं समझा तो आपका जीवन नर्क हो जाएगा. पहले आप समझें कि मधुमेह क्यों होता है. आपको भ्रम है कि आप मीठा खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं. आपको जानना होगा कि सिर्फ मीठी चीज से ही डायबिटीज नहीं होगा. आप जो भी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है. चावल, गेहूं, मक्का और साबूदाना आदि में 70 प्रतिशत या इससे भी अधिक कार्बोहाइड्रेट है. तात्पर्य यह कि जो खाना आप खा रहे हैं, उसमें 70 प्रतिशत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है. नियमतः, यह 40-45 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

जब हम खाते हैं तो खाद्य पदार्थ से शुगर भोजन की नली द्वारा हमारे खून में चला जाता है. हमारी पैंक्रियाज ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन को खून में उड़ेल देती है. इंसुलिन, शुगर को पकड़कर हमारी करीब 60 खरब कोशिकाओं में पहुंचाता है. कोशिकाएं शुगर को अपने माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में जमा कर लेती हैं. हमारे जिंदा रहने के लिए शुगर अति आवश्यक है. समस्या तब उत्पन्न होती है, जब हम दिन-भर कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाते रहते हैं. अधिक शुगर खाने पर हमारी पैंक्रियाज ग्रंथि को अधिक इंसुलिन बनाना पड़ता है. यह प्रक्रिया सालों-साल चलती रहती है. शुगर को कोशिकाओं में डालने के लिए पैंक्रियाज को अधिक-से-अधिक इंसुलिन बनाना पड़ता है. एक स्थिति ऐसी आती है, जब हमारी कोशिकाएं शुगर से पूरी तरह भर जाती हैं और वे इंसुलिन के शुगर को लेना बंद कर देती हैं. अब इंसुलिन आपके शुगर को लेने के लिए लिवर की खुशामद करता है. आपका लिवर उसे वसा में बदलकर आपके शरीर के विभिन्न भागों में जमा कर देता है. आपकी तोंद निकलने लगती है. इसे 'इंसुलिन रेजिस्टेंस' कहते हैं जो मधुमेह का प्रमुख कारण है. अब आपके खून में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है. खून में शुगर भी बढ़ जाता है. इस तरह, आपको लगता है कि आप डायबिटीज से ग्रसित हो गए हैं. लिवर जब तक शुगर को वसा में परिवर्तित कर रहा है, आपका खाली पेट और खाना खाने के बाद शुगर का लेवल एवं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन ठीक रहता है. आप समझते हैं कि आपको डायबिटीज नहीं है. यहीं पर आप भारी भूल में हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस साल-दर-साल चलता है और जांच के बाद आपके शुगर का स्तर भी ठीक आता है. इसे 'प्री-डायबिटीज स्टेज' कहते हैं. अगर, आप प्री-डायबिटीज स्टेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस को पकड़ लें तो मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं. प्री-डायबिटीज की स्थिति को आप एक साधारण जांच से पकड़ सकते हैं. आप वर्ष में दो बार खाली पेट शुगर एवं इंसुलिन की जांच करवा लें. अगर, इंसुलिन का लेवल सात से ज्यादा है तो यह खतरे की घंटी है. आपकी सतर्कता आपको मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी से बचा सकती है.

नोट : पत्रिका के अगले अंक में इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप कैसे दूर करें, बताया जाएगा. ■

बच्चियों को उम्र से पहले पीरियड्स

कारण, लक्षण और उपचार

"समय से पहले प्यूबर्टी आने से बच्चियों की कद-काठी बढ़ने से रुक सकती है. यह स्थिति मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह प्रभावित करती है. कम उम्र में प्यूबर्टी आगे चलकर लंबे समय तक रहनेवाली कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह भी बन सकती है."

अमृता कुमारी

एक समय ऐसा था, जब बच्चियों को बड़ा होता देख हर मां एक तय उम्र सीमा पर आनेवाले शारीरिक बदलावों के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया करती थी. आज वक्त कुछ ऐसा आ गया है कि उनके मानसिक रूप से संभलने से पहले ही वो शारीरिक रूप से परिपक्व हो जा रही हैं. यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि बेहद ही संवेदनशील और चिंताजनक विषय है, जिसपर सभी माता-पिता को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

आजकल अक्सर ऐसे मामले सामने आने लगे हैं, जिनमें 8 से 11 साल तक की बच्चियों को पीरियड्स (मासिक धर्म) आने शुरू हो गए. जिस उम्र में बेफिक्र होकर उन्हें अपनी पढ़ाई, खेलकूद और विभिन्न क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान देना था, उस उम्र में वो पीरियड्स की असहनीय पीड़ा, संभलकर चलने, उठने-बैठने और सेनेटरी नैपकिन संभालने की जद्दोजहद में उलझकर रह गईं. आखिर इनसब के पीछे की वास्तविकता क्या है? आखिर क्यों हमारी बच्चियों में उम्र से पहले शारीरिक यौवन दिखाई देने लगा है?

आजकल की मिलावटी खाद्य सामग्री, अति व्यस्त जीवनशैली और पोषण में बदलाव के कारण बच्चियों में पीरियड्स 9 से 12 साल की उम्र में शुरू होना सामान्य होता जा रहा है. पीरियड्स का किशोरावस्था में आना एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन 9 साल से पहले पीरियड्स का शुरू होना असामान्य अवस्था है, जिसे 'प्रीकॉशियस प्यूबर्टी' कहा जाता है.

ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है. इस दौरान उन्हें भावनात्मक सहयोग, संतुलित आहार और स्वच्छता के बारे में समझाना बेहद जरूरी है.

प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के प्रमुख कारण

मोटापा, अनियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों में कमी, पारिवारिक इतिहास, ऑटोइम्यून बीमारी, असंतुलित हॉर्मोन, पोषण की कमी, खाने में जंक फूड की अधिकता, कोल्ड ड्रिंक का सेवन, अधिक स्क्रीन टाइम और इंटिमेट सीन देखना, तनाव और दोस्तों का चुनाव आदि प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के मुख्य कारण हैं.

प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के प्रमुख लक्षण

अचानक से व्यवहार परिवर्तन, स्तनों का उभरना, शारीरिक परिवर्तन, अवसाद और अकेलापन जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ध्यान देना जरूरी है.

क्या करें अभिभावक

बातचीत करें और समझाएं : बच्चियों को समझाएं कि यह एक सामान्य शारीरिक बदलाव है, इसमें डरने की बात नहीं है. उन्हें मानसिक रूप से इसका सामना करना सिखाएं. प्यार और फिक्र, दोनों ही महसूस कराएं, ताकि वो खुलकर अपनी बात आपसे बता पाएं.

स्वच्छता : सैनिटरी पैड का उपयोग करना सिखाएं और उन्हें हर 4 से 6 घंटे में बदलने के लिए कहें. कपड़ों और अंडरगारमेंट की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.

डॉक्टर की सलाह : यदि 8 वर्ष से पहले लक्षण दिखें या दर्द बहुत अधिक हो तो तुरंत ही किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें.

पौष्टिक आहार सबसे जरूरी : छोटी उम्र से ही बच्चियों को कैल्शियम और आयरन से भरपूर भोजन दें, ताकि आगे चलकर उनमें पोषक तत्वों की कमी न हो और वो स्वस्थ रह सकें.

पीरियड्स के दौरान ये खाएं

आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ : पालक, मेथी, ब्रोकली, चुकंदर, दालें और फलियां जो शरीर में आयरन की कमी को पूरा करते हैं.

फल और सब्जियां : पपीता (पेट के लिए अच्छा), केला (पोटेशियम), सेब और सिट्रस फल जैसे संतरा और नींबू (आयरन और विटामिन सी अवशोषण के लिए).

ओमेगा-3 फैटी एसिड : अलसी के बीज, अखरोट और मछली (अगर आप मांसाहारी हैं) दर्द और ऐंठन को कम करने में मदद करते हैं.

प्रोटीन और स्वस्थ वसा : अंडे, दही, एवोकाडो और डार्क चॉकलेट (70 प्रतिशत से अधिक कोको) मूड को बेहतर बनाते हैं और थकान कम करते हैं.

अदरक और हल्दी : अदरक की चाय या अदरक के पानी से दर्द को कम करने में मदद मिलती है.

इन चीजों से रखना है परहेज

जंक फूड और प्रोसेस्ड खाना : चिप्स, पिज्जा, समोसा जैसी तली-भुनी चीजें सूजन बढ़ा सकती हैं.

ज्यादा चीनी और नमक : मीठी चीजों और नमक के अधिक सेवन से पेट का फूलना बढ़ सकता है.

कैफीन : कॉफी, चाय और चॉकलेट से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी और पेट में एसिडिटी कर सकते हैं.

कार्बोनेटेड पेय : सोडा और कोल्ड ड्रिंक जो पेट में गैस पैदा करते हैं.

परामर्श

हाइड्रेटेड रहें, दिन-भर खूब पानी पिएं. हल्का और पौष्टिक खाना खाएं. अगर दर्द ज्यादा हो तो हल्के गर्म पानी से सिंकाई करें या डॉक्टर से सलाह लें. पेनकिलर का इस्तेमाल करने से बचें. हल्के योगाभ्यास करें, जिससे पीरियड्स क्रैंप और अधिक रक्तस्राव में राहत मिल सके. ■

> फीफा विश्व कप केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को जोड़नेवाला एक सांस्कृतिक उत्सव भी है. यह आयोजन वैश्विक स्तर पर सीमाओं और भाषाओं से परे जाकर इंसानी जज्बे, एकता और उत्कृष्टता का प्रतीक बनता है. हर चार साल बाद यह अनगिनत यादें और प्रेरणास्पद कहानियां छोड़ जाता है.

फीफा विश्व कप 2026

फुटबॉल का महाकुंभ और नए युग की शुरुआत

फुटबॉल केवल एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, जुनून और सपनों का प्रतीक है. जब भी फीफा विश्व कप का आयोजन होता है, पूरी दुनिया कुछ सप्ताह के लिए एक ही मंच पर आ जाती है. वर्ष 2026 का फीफा विश्व कप भी इसी भावना का अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आया. इस बार का विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक रहा. पहली बार यह प्रतियोगिता तीन देशों- अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हुई. साथ ही, पहली बार 48 टीमों ने इसमें भाग लिया, जिससे प्रतियोगिता और भी अधिक रोमांचक, प्रतिस्पर्धी तथा वैश्विक बन गई. इस विश्व कप ने यह सिद्ध कर दिया कि फुटबॉल की लोकप्रियता किसी सीमा या भाषा की मोहताज नहीं है. स्टेडियमों में लाखों दर्शकों की मौजूदगी और दुनिया-भर में अरबों लोगों द्वारा टीवी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच देखना इस खेल की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है.

विश्व कप 2026 में पारंपरिक दिग्गज टीमों के साथ-साथ कई नई और उभरती हुई टीमों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. छोटे देशों के खिलाड़ियों ने यह साबित किया कि प्रतिभा केवल बड़े देशों तक सीमित नहीं होती. कई मुकाबले अंतिम मिनट तक रोमांच से भरपूर रहे, जिससे दर्शकों की उत्सुकता लगातार बनी रही. इस विश्व कप का सबसे बड़ा आकर्षण फाइनल मुकाबला रहा, जिसमें स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया. पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने अनुशासित खेल, बेहतरीन टीमवर्क और शानदार रणनीति का प्रदर्शन किया. वहीं, अर्जेंटीना ने भी फाइनल तक का सफर तय कर अपने जुझारू खेल का परिचय दिया. इस विश्व कप में कई युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने यह संदेश दिया कि खेलों में उम्र नहीं बल्कि प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. दूसरी ओर, कई अनुभवी खिलाड़ियों ने अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता से अपनी टीमों को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला.

खलील अहमद

तकनीक ने भी इस विश्व कप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वीडियो असिस्टेंट रेफरी, गोल-लाइन तकनीक और उन्नत डेटा विश्लेषण ने निर्णयों को अधिक सटीक और निष्पक्ष बनाया. इससे विवादों में कमी आई और खेल की पारदर्शिता बढ़ी. आधुनिक

तकनीक ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने में भी बड़ी भूमिका निभाई. विश्व कप 2026 केवल खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी व्यापक रहा. मेजबान देशों में पर्यटन को बढ़ावा मिला, लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए और स्थानीय व्यापार को भी काफी लाभ हुआ. विभिन्न देशों से आए दर्शकों ने अपनी संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली का परिचय देकर वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत किया. आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने विश्व कप के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया. मैचों की प्रमुख झलकियां, खिलाड़ियों के इंटरव्यू, प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं और विश्लेषण कुछ ही क्षणों में पूरी दुनिया तक पहुंचने लगे. इससे युवा वर्ग की भागीदारी और रुचि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई.

भारत भले ही अभी तक फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया है, लेकिन भारतीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति उत्साह लगातार बढ़ रहा है. विश्व कप के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में मैच देखने के लिए विशेष आयोजन किए गए. केरल, प. बंगाल, गोवा और पूर्वोत्तर के राज्यों में फुटबॉल का जुनून विशेष रूप से देखने को मिला. यह उम्मीद की जा रही है कि आनेवाले वर्षों में भारत भी विश्व फुटबॉल में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा. विश्व कप हमें केवल जीत और हार का पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व, धैर्य और संघर्ष का भी संदेश देता है. मैदान पर अलग-अलग देशों के खिलाड़ी पूरी ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन मैच समाप्त होने के बाद एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. यही खेल भावना विश्व शांति और वैश्विक भाईचारे की प्रेरणा देती है. इस विश्व कप ने यह भी साबित किया कि खेल समाज को जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है. अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक ही टीम के समर्थन में एकसाथ खड़े दिखाई दिए. यही खेल की सबसे बड़ी शक्ति है.

फीफा विश्व कप 2026 ने जहां खेल जगत को नई ऊर्जा और प्रेरणा दी, वहीं इसके कुछ ऐसे पहलू भी सामने आए, जिनपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है. सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो इस विश्व कप ने खेल भावना, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक विविधता को मजबूत किया. नए प्रारूप के कारण अधिक देशों को विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला. मेजबान देशों की अर्थव्यवस्था को पर्यटन, होटल उद्योग, परिवहन और स्थानीय व्यापार के माध्यम से बड़ा लाभ हुआ. आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने खेल को अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया. साथ ही, इस प्रतियोगिता ने दुनिया-भर के युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित किया और उन्हें अनुशासन, टीमवर्क तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संदेश दिया.

वहीं, नकारात्मक पक्षों की बात करें तो कुछ रेफरिंग निर्णयों और वीएआर को लेकर विवादों ने खेल की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़े किए. फिर, 48 टीमों के प्रारूप के कारण प्रतियोगिता की अवधि लंबी होने से खिलाड़ियों पर शारीरिक और मानसिक दबाव भी बढ़ा. अत्यधिक व्यवसायीकरण, महंगे टिकट, प्रसारण अधिकारों की प्रतिस्पर्धा तथा विज्ञापनों की बढ़ती भूमिका ने कई बार खेल की मूल भावना पर भी बहस छेड़ी. इनके अतिरिक्त, सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों और रेफरियों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां तथा ट्रोलिंग जैसी घटनाएं खेल संस्कृति के लिए चिंता का विषय रहीं. इस प्रकार, आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो फीफा विश्व कप 2026 उपलब्धियों और चुनौतियों, दोनों का संगम रहा. भविष्य में यदि पारदर्शी रेफरिंग, खिलाड़ियों के कार्यभार का संतुलन, तकनीक का बेहतर उपयोग तथा खेल भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तो विश्व कप और भी अधिक निष्पक्ष, प्रेरणादायक और सफल बन सकता है.

अंततः, फीफा विश्व कप 2026 इतिहास के सबसे यादगार विश्व कप आयोजनों में से एक बन गया. नए प्रारूप, नई प्रतिभाओं, रोमांचक मुकाबलों और शानदार आयोजन ने इसे विशेष बना दिया. स्पेन की ऐतिहासिक जीत, अर्जेंटीना का संघर्ष, नई टीमों का शानदार प्रदर्शन और तकनीक का प्रभावी उपयोग आनेवाले वर्षों तक फुटबॉल प्रेमियों की स्मृतियों में बना रहेगा. फुटबॉल हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन, टीमवर्क और अटूट आत्मविश्वास से प्राप्त होती है. यही कारण है कि फीफा विश्व कप केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि पूरी मानवता को जोड़नेवाला एक वैश्विक उत्सव है. आनेवाले विश्व कप का इंतजार अब से ही दुनिया-भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों को रहेगा. ■

रसिका दुग्गल

दमदार अभिनय से मचा रहीं धूम

> रसिका ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है. छोटे शहर जमशेदपुर से बड़े पर्दे तक का उनका सफर मेहनत, लगन और हिम्मत की कहानी है.

आजकल ओटीटी पर सर्वाधिक चर्चित एक्ट्रेस की फेहरिस्त में शुमार है एक नाम- रसिका दुग्गल. रसिका ने लोकप्रिय वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में बीना त्रिपाठी (बीना भाभी) और 'दिल्ली क्राइम' में नीति सिंह के किरदार से न सिर्फ अपनी गंभीर और सजग अदाकारी का लोहा मनवाया है, बल्कि अपनी बहुआयामी प्रतिभा से सबका दिल भी जीता है.

अब रसिका दुग्गल सितंबर में आनेवाली फिल्म 'मिर्जापुर : द मूवी' में एक दमदार रोल में दिखाई देंगी. इस फिल्म में उन्होंने अपनी गंभीर और बोल्ड एक्टिंग से दर्शकों के पसीने छुड़ाने की पूरी तैयारी कर ली है. रसिका पर फिल्माए गए इंटीमेट बेड सीन को जब फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर दिखाया गया तो मानो जैसे फिल्म की सफलता की गारंटी मिल गई. बता दें कि 'मिर्जापुर' वेब सीरीज के सभी तीन सीजन बेहद सफल रहे हैं और यही वजह है कि फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. फिल्म की रिलीज के बाद वेब सीरीज का चौथा सीजन भी आएगा.

यूं मिला 'बीना भाभी' का किरदार

एक्ट्रेस रसिका दुग्गल को 'मिर्जापुर' सीरीज में बीना त्रिपाठी का रोल मिलने का किस्सा बड़ा रोमांचक है. रसिका ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि काम मांगने के लिए उन्होंने निर्देशक करण अंशुमन को मैसेज किया था, जिसके बाद उनका ऑडिशन हुआ और उन्हें यह मशहूर किरदार मिल गया. रसिका ने बड़ी हिम्मत कर 'मिर्जापुर' के डायरेक्टर को काम के लिए एक टेक्स्ट मैसेज किया था और सेलेक्शन होने के बावजूद वो डरी रहती थीं कि कहीं उन्हें इस रोल के लिए मना न कर दिया जाए.

जन्म और शिक्षा

झारखंड के जमशेदपुर (उस वक्त बिहार) की रहनेवालीं रसिका का जन्म 17 जनवरी 1985 को हुआ. साल 2004 में उन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन से मैथ में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली. इसके बाद रसिका ने सोफिया पॉलिटेक्निक से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया. फिर, अभिनय में रुचि को देखते हुए उन्होंने पुणे के एफटीआईआई से एक्टिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया.

कैरियर और शादी

उधार के कपड़ों में ऑडिशन देकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानेवाली रसिका दुग्गल ने साल 2007 में बॉलीवुड फिल्म 'अनवर' में एक चरित्र किरदार से अपने कैरियर की शुरुआत की. इस फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें मात्र तीन हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया गया था. साल 2008 में उन्होंने फिल्म 'तहान' किया. टीवीएफ की वेब सीरीज 'परमानेंट रूममेट्स' सीजन-2 में उन्होंने कैमियो रोल निभाया. इसके बाद टीवीएफ की ही एक अन्य सीरीज 'ह्यूमरसली योर्स' (2017) में काम किया. इसमें उनके साथ कॉमेडियन विपुल गोयल थे. साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म 'तू है मेरा संडे' में उन्होंने कैमियो रोल किया. फिल्म में बरुन सोबती, विशाल मल्होत्रा, सहाना गोस्वामी, नकुल भल्ला, अविनाश तिवारी और जय उपाध्याय मुख्य भूमिका में थे. इनके अलावा रसिका फिल्म 'औरंगजेब', 'किस्सा', 'मंटो' और 'लूटकेस' में भी नजर आ चुकी हैं.

बिनोद कुमार

निजी जिंदगी की बात करें तो रसिका दुग्गल की शादी अभिनेता मुकुल चड्ढा से हुई है. शादी के बाद भी वह लगातार फिल्मों और वेब सीरीज में व्यस्त हैं. इंस्टाग्राम पर रसिका के प्रशंसकों की संख्या लाखों में है.

जमशेदपुर से गहरा लगाव

इतनी सफलता मिलने के बावजूद रसिका दुग्गल अक्सर अपने इंटरव्यू में जमशेदपुर को याद करना नहीं भूलतीं. वह कहती हैं कि इस शहर ने उन्हें सादगी, अनुशासन और जमीन से जुड़े रहने की सीख दी. टाटानगर की सड़कों, जुबली पार्क की हरियाली और यहां के शांत जीवन ने उन्हें हमेशा मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच दी. रसिका मानती हैं कि छोटे शहर में पले-बढ़े होने की वजह से ही वह किरदारों को अधिक संवेदनशीलता के साथ निभा पाती हैं.

रसिका दुग्गल केवल एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि जमशेदपुर की उस पहचान का हिस्सा भी हैं जो दिखाती है कि छोटे शहरों से निकलकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं. आज जब लोग उन्हें 'मिर्जापुर' की बीना त्रिपाठी के रूप में देखते हैं तो टाटानगर के लिए यह गर्व की बात है कि इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जानेवाली कलाकार की जड़ें इसी शहर की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं. ■

BUILDING
TRUST,
CONSTRUCTING
FUTURES

MITHILA NAGRI

PROPERTY DEALING & CONSTRUCTION

आपका सपना, हमारी जिम्मेदारी

भरोसे के साथ, बेहतर भबिष्य की ओर

OUR SERVICES

PROPERTY BUYING & SELLING
Find your dream property or sell with the best deal.

LAND & PLOT DEALS
Residential, Commercial & Investment Plots Available.

HOUSE CONSTRUCTION
From planning to possession – We build quality, you live happily.

REGISTRATION ASSISTANCE
Complete support in property registration & documentation.

WHY CHOOSE US?

- TRUST & TRANSPARENCY
- EXPERIENCED TEAM
- QUALITY CONSTRUCTION
- BEST VALUE FOR YOUR INVESTMENT

Let's Build Your

DREAM TOGETHER!

CALL US
9708460162
7903337614

EMAIL US
nagrimithila@gmail.com

VISIT OUR WEBSITE
mithilaNagri.com

RESIDENTIAL | COMMERCIAL | PLOTS | CONSTRUCTION

TRUST | TRANSPARENCY | GROWTH

Dr. Zakir Hussain Teachers' Training College

LAHERIASARAI, DARBHANGA, 846003 (BIHAR)

Permanent Recognition by the Govt. of Bihar , ERC , NCTE , Bhubneshwar,
Regd. Under 2(f) UGC, New Delhi and Accredited to 'B' Grade by NAAC
Affiliated to L.N. Mithila University, Darbhanga

Fax & Ph. # 06272-233441 Website-www.zhttc.org

Dr. Sharique Hussain
Secretary

Prof. M. Hassan
Principal